सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 91, नई दिल्ली । बुधवार, 12 जून 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते।

03 200 कांवड़ शिविर लगाएगी केजरीवाल सरकार
06 विपक्ष की गारंटियों के बावजूद एनडीए को बहुमत
08 निरंतरता, अनुभव और उत्साह का संगम है केंद्रीय मंत्रिमंडल

हर्ष मल्होत्रा बने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, दिल्ली को मिलेगी जाम से मुक्ति?

मोदी 3.0 टीम में दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। जहां एक तरफ एक्सप्रेसवे समेत अन्य योजनाओं के गति पकड़ने के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली को जाम से मुक्ति मिलेगी।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। एनसीआर को जाम की समस्या से निजात मिलने की आस जग गई है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं एनसीआर में चल रही है, जिससे ट्रैफिक जाम से लोग पार पा सकेंगे। इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे, अर्बन एक्सटेंशन-2, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई कनेक्टर और कटरा एक्सप्रेस-वे शामिल है।

साथ ही एलिवेटेड रोड की योजना बनी है। एलिवेटेड रोड वर्तमान सड़क से ऊपर उठकर चलेगा और हल्के वाहन इस एलिवेटेड रोड से आवागमन कर सकेंगे। पॉड टैक्सी भी चलाने की योजना है। दरअसल यह आस एनसीआर के लोगों को तब जगी है जब पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है।

लोगों को उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस महत्वकांक्षी योजना को बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री वह सहयोगी हर्ष मल्होत्रा रफ्तार देंगे। फिलवक्त धौला कुआं से मानेसर, गुरुग्राम तक बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना रहता है। इसके चलते घंटों जाम में फंसकर लोगों को परेशान होना पड़ता है। इसे ही देखते हुए पिछले कार्यकाल में नितिन गडकरी ने योजना

तैयार की ताकि जाम से मुक्ति मिल सके। इनमें मुख्य रूप से पांच परियोजनाएं शामिल है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे अक्षरधाम से शुरू होगा और सिग्नेचर ब्रिज, गीता कॉलोनी होते हुए बागपत के रास्ते देहरादून तक जाएगा। इसके चालू होने से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दबाव कम होगा। इस योजना को भी धार देने में हर्ष सहयोगी बन सकेंगे। इसी तरह द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा आठ लेन वाला एक्सप्रेसवे है। दिल्ली में 10 किलोमीटर के हिस्से का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है।

इसके खुलने से दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर चढ़कर वाहन सीधे दिल्ली से बाहर निकलेगी। अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 योजना के तहत फरीदाबाद से सिंघु बॉर्डर तक जाएगा। इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। इसके अलावा कटरा एक्सप्रेसवे योजना है। दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर प्रतिदिन करीब डेढ़ लाख वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। एक्सप्रेसवे कनेक्टर जो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को दिल्ली से जोड़ेगा। 60 किलोमीटर लंबा है। वाहन आश्रम के पास इस कनेक्टर से चढ़ेंगी और सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाएंगी।

बिना चालक वाली पॉड टैक्सी योजना को भी मिलेगी रफ्तार

बिना चालक वाली पॉड टैक्सी भी चलाने की योजना केंद्र सरकार की है। पिछले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी औपचारिक घोषणा भी की थी। लाल कुंआ और मानेसर के बीच बिना चालक वाली टैक्सी दौड़ेगी। यह करीब 13 किलोमीटर वाला ट्रैक प्रस्तावित है। जो दिल्ली, गुरुग्राम बार्डर से बादशाह पुर मोड सोहना रोड तक होगी। इस पर करीब 850 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

सार्वजनिक परिवहन परियोजना मेट्रिनो के निर्माण के लिए निविदाएं भी मिली थी। यह परियोजना धौलाकुंआ से हरियाणा के मानेसर के बीच 70 किलोमीटर मार्ग को जोडेगी। इससे एनसीआर में यातायात सुगम होगा। मेट्रिनो एक चालक रहित परिवहन प्रणाली है जो रोपवे पर चलती है। इसके साथ ही दिल्ली-जयपुर मार्ग में इलेक्ट्रिक बस दौड़ाने की भी योजना है।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा: परिवहन विशेष वालंटियर शाला अभियान

रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन के साथ मिलकर ₹सड़क सुरक्षा जीवन रक्षाः परिवहन विशेष₹ वालंटियर शाला अभियान का आयोजन कर रहा है। इस पहल के तहत, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत या संस्थागत स्तर पर जो भी कदम उठाए हैं, कृपया हमें उनके बारे में बताएं। आपके इन महत्वपूर्ण प्रयासों को हम प्रकाशित करेंगे ताकि और लोग प्रेरित हो सकें।

सड़क सुरक्षाः सबसे महत्वपूर्ण

सड़क सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यह न केवल हमारी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे आस-पास के लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित यात्रा के अनुभव को बढ़ावा देने के लिए यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

बनें सड़क सुरक्षा वालंटियर

हमारी वालंटियर शाला अभियान के तहत, हम ऐसे इच्छुक उम्मीदवारों की तलाश में हैं जो हमारे वालंटियर कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से, वालंटियरों को सड़क सुरक्षा और इससे संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर विशेष प्रशिक्षण और जानकारी दी जाएगी। आप भी हमारे सड़क सुरक्षा वालंटियर बन सकते हैं और इस महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बन सकते हैं।

कैसे करें आवेदन ?

आपके द्वारा उठाए गए किसी भी सड़क सुरक्षा पहल या कार्यक्रम की जानकारी हमें निम्नलिखित ईमेल आईडी पर भेजें: [roadsafetysquad@gmail.com] आपके इनपुट न केवल हमें प्रेरित करेंगे बल्कि उन्हें व्यापक रूप से साझा करके दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।

हमारी पहल ₹सड़क सुरक्षा जीवन रक्षाः परिवहन विशेष₹ का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के महत्व को उजागर करना और इसे समाज में एक आंदोलन के रूप में स्थापित करना है। आपका सहयोग और सहभागिता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

आपके प्रयासों और समर्थन के लिए धन्यवाद।

डॉ अंकुर शरण, राष्ट्रीय मुख्य परिवहन एवं योजना अधिकारी
रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.)
roadsafetysquad@gmail.com

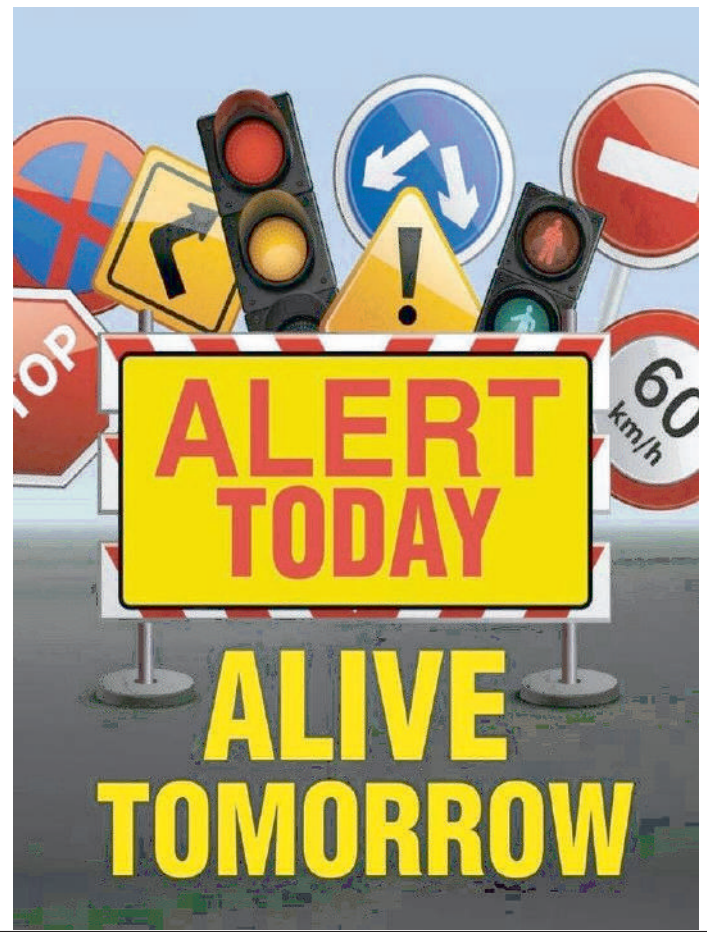

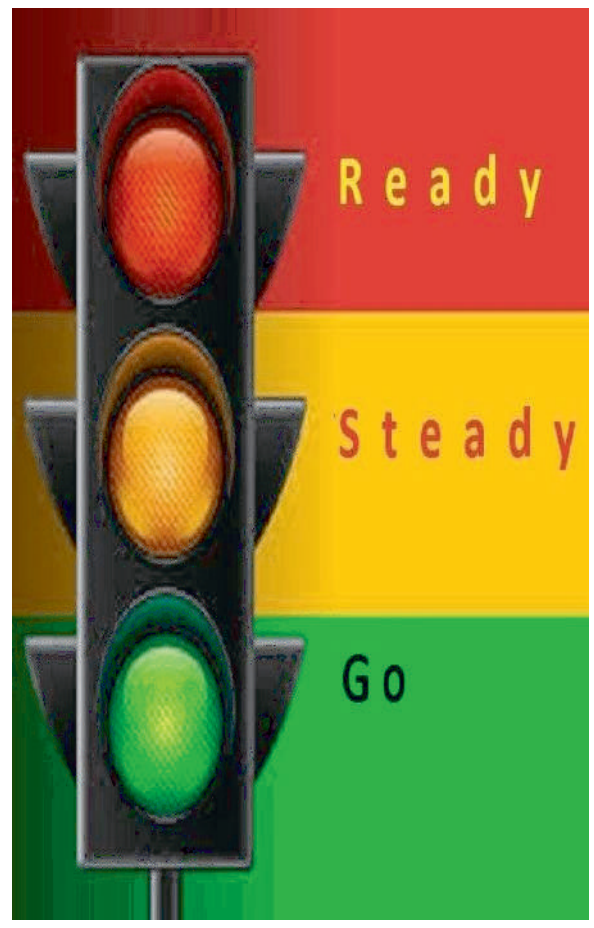

परिवहन विशेष
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र
प्रस्तुत

पुरस्कार सम्मान समारोह

ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू

दिनाक : 06 जुलाई 2024 समय : 4 p.m.
स्थान : कांस्टीट्यूशन क्लब आफ इंडिया, रफी मार्ग नई दिल्ली 110001

मुख्य अतिथि : जस्टिस श्री सतीश चंद्रा (रिटायर्ड)

प्राप्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित श्रेणियां:-

1. सड़क सुरक्षा 2. विशेष योगदान (पर्यावरण संरक्षण/पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलर) 3. वाहन निर्माता/ डीलर 4. परामर्श विशेषज्ञ (परिवहन) 5. विशेष योगदान (परिवहन सुरक्षा/व्यवस्था) 6. विशेष योगदान (वाहन चालक/मालिक) 7. विशेष योगदान (कानून/न्याय/न्यायालय/अधिवक्ता) 8. विशेष योगदान (चिकित्सा) 9. योगदान सम्मान पुरस्कार (सेवानिवृत्त अधिकारी) 10. मीडिया/रिपोर्टर

3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, A-4 पश्चिम विहार, नई दिल्ली : 110063
सम्पर्क : 9212122095, 9811732095
www.newsparivahan.com, www.newstransport.in
Info@newsparivahan. com, news@newsparivahan.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

Office of Deputy Commissioner of Police
Traffic, Faridabad
Sector-12, Faridabad
Email id-dcptraffic.fbd-hry@nic.in
Telephone No. 0129-2222223

ट्रैफिक एडवाइजरी

जिला फरीदाबाद में दैनिक रूप से घटित हो रहे यातायात जाम सम्बन्धी समस्याओं को मध्यनजर रखते हुए नागरिकों के सुविधाजनक गंतव्य तथा यातायात के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा शहर के ट्रैफिक जाम से ग्रस्त मुख्य स्थानों का सर्वे किया जा रहा है। जिसके अनुसार फरीदाबाद शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। अतः सभी नागरिक जिला फरीदाबाद में यातायात के बेहतर संचालन और सुगम गंतव्य हेतु निम्नलिखित विन्दुओं का अनुसरण करते हुए यातायात पुलिस का सहयोग करें।

सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है की यातायात पुलिस के सर्वे के दोरान चिन्हित जामग्रस्त स्थानों या फरीदाबाद शहर में यदि किसी भी स्थान पर आपको ट्रैफिक जाम पाया जाता है तो आप इसकी सूचना डायल 112, ट्रैफिक कन्ट्रोल रूम तथा थाना यातायात फरीदाबाद एवम् सम्बंधित जोन के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को नीचे दिए गये फ़ोन नंबर पर संपर्क करके दे सकते है। इसके साथ साथ ट्रैफिक जाम की स्थिति में जाम की विडिओ/फोटो यातायात पुलिस के सोशल मीडिया Twitter अकाउंट- @FTPfbd तथा Facebook अकाउंट –Faridabad Traffic Police पर भी भेज सकते है। तथा जाम को खुलने में कितना समय लगा इसके बारे में अपना फीड बैक भी सोशल मीडिया व पुलिस कंट्रोल रूम को अवश्य दे ताकि आप द्वारा दी गई फीड बैक का अवलोकन उपरान्त यातायात पुलिस द्वारा जाम ग्रस्त स्थान पर तुरंत प्रभाव से सम्बंधित ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को नियुक्त करके ट्रैफिक जाम को खुलवाया जा सके तथा आपको किसी भी स्थान पर 5/7 मिनट से ज्यादा यातायात जाम की स्थिति का सामना ना करना पड़े।

1. यातायात जाम की स्थिति में नागरिक निम्नलिखित मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।

S.NO	Location	Officer Name	Mobile no.
1	➢ Ajronda chowk	Insp. Naresh kumar T.I	9416839769
	➢ Old chowk	EASI Anil kumar ZO-3	9871979896
	➢ Badkhal chowk	ASI Rajender ZO-01	8708274962
	➢ Mewla maharajpur		
	➢ Badarpur border		
	➢ Sector 28/29 Chowk		9810371459
	➢ Sector 37 bypass road	ESI Mahesh kumar ZO-2	
	➢ Traffic victor 1	ESI Jagdish chand	7838424348
	➢ Traffic victor 2	EHC Mahipal	9711198922
2	➢ Ballabhgarh bus stand	Insp Jagbir singh T.I	9582808640
	➢ Sohna T-Point	ASI Prem parkash ZO-7	8168484554
	➢ 8/3 Chowk	ASI Bijender ZO-06	7840850046
	➢ Gupta hotel road	ESI Anil kumar ZO-10	9971893073
	➢ Jcb chowk	ASI Anil kumar ZO-08	8383887072
	➢ Traffic victor 3	EHC Rajkumar	8860802700
	➢ Traffic victor 4	EHC Ravinder	8800789796
	➢ Traffic victor 6	EHC Shivdutt	8285098100
3.	➢ Sainik colony road	Insp Darpan TI NIT	8920400045
	➢ Masjid chowk	ASI Anup singh ZO-16	9467718604
	➢ 1/2 chowk, Main market	ASI Rajender ZO-15	8510824100
	➢ Metro chowk,RK hospital		
	➢ Hardware chowk	EASI Manoj kumar ZO-13	9811175601
4.	➢ Palla pull	Insp Satish kumar T.I	8684848608
	➢ Sehatpur naya pull		
	➢ Agra sweets(nahar par road)	ESI Suresh ZO-19	9868099680
	➢ Traffic victor 5	EHC Ashok	9899145491
5.	Traffic control room helpline	DRO Faridabad	0129-2267201
6.	SHO Traffic	Insp. Vinod kumar	9582200138

फिटनेस को लेकर बढ़ती उम्र कर कर रही परेशान, अपनी जीवनशैली में शामिल करें हैल्दी डाइट

महिलाएं अक्सर अपने खानपान का ध्यान नहीं रखती हैं. अगर आपकी उम्र 40 की हो गई है तो आपको कुछ जरूरी पोषक तत्वों को डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. खासकर ओमेगा-3, प्रोटीन आदि से भरपूर चीजों का सेवन जरूर करें. इससे आप हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, खून की कमी जैसी समस्याओं से बची रह सकती हैं.

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है शरीर के अंग कमजोर होने लगते हैं. ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप कम उम्र से ही पोषक तत्वों से भरपूर चीजों का सेवन करें. साथ ही बढ़ती उम्र में भी उन सभी विटामिंस, मिनरल्स आदि को डाइट में शामिल करें, जो संपूर्ण सेहत के लिए जरूरी होते हैं. आपको बुजुर्गावस्था में बीमारियों से बचाए रखें. यह बात महिलाओं पर भी लागू होता है. खासकर, जब आपकी उम्र 40 पार हो रही हो तो आयरन, ओमेगा-3, प्रोटीन आदि से भरपूर चीजों का सेवन जरूर करें. अक्सर महिलाओं को पता नहीं होता है कि उन्हें 40 वर्ष की उम्र में कौन-कौन से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. आइए जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा से, जिन्होंने हाल ही में 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं के लिए कुछ आवश्यक न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक महत्वपूर्ण पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. जानें, उनके अनुसार आपको इस उम्र के पड़ाव में क्या-क्या डाइट में शामिल करना चाहिए.

1. प्रोटीन

न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा का कहना है कि महिलाओं को 40 वर्ष की उम्र में प्रोटीन का सेवन जरूर करना चाहिए. इस उम्र में मेनोपॉज होने के पहले कई तरह के हॉर्मोनल बदलाव भी होते हैं. कई बार शरीर में फैट बढ़ जाता है, लीन मसल मास में कमी आ जाती है, जो बाद में उनके दीर्घायु को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि आप प्रोटीन का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें. यह लीन मसल्स के नुकसान को रोकने में मदद कर सकता है.

5 आदतों को डेली लाइफ में शामिल करें
महिलाएं, खूबसूरती में आएगा निखार, बन जाएंगी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी

2. बी विटामिन

40 से अधिक की उम्र वाली महिलाओं के लिए बी-विटामिन श्रृंखला वाले विटामिंस भी बेहद जरूरी हैं. आप जो भी खाती हैं, उस भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने या बनाने के लिए आपके शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया में ये बी-विटामिन काफी मदद करते हैं. साथ ही लाल रक्त कोशिकाओं को भी बनाने में मदद करते हैं.

3.कैल्शियम

जैसे-जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, उनकी हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखता है. कैल्शियम के सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम किया जा सकता है. यह एक ऐसी बीमारी है, जिसमें हड्डियां भंगुर (brittle) हो जाती हैं. कैल्शियम की जरूरत मांसपेशियों के संकुचन, नर्व, हार्ट के कामकाज और अन्य जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसे शरीर के अन्य बुनियादी कार्यों के लिए भी होती है. यदि आप अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम शामिल नहीं करती हैं तो शरीर आपकी हड्डियों से कैल्शियम चुराने लगता है, जिससे हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं.

4. विटामिन डी

महिलाओं के लिए विटामिन डी भी बेहद जरूरी है. यह कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, इसलिए इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आप 40 की उम्र में आकर विटामिन डी भरपूर लें. साथ ही, विटामिन डी डायबिटीज, हृदय रोग सहित अन्य समस्याओं को कम करने में भी बेहद फायदेमंद होता है.

5. आयरन

क्या आप जानती हैं कि आपके शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है? यह एक ऐसा पदार्थ है, जो आपके लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है. 40 की उम्र ज्यादातर महिलाओं के लिए पेरिमेनोपॉज पीरियड का होता है. ऐसे में आयरन की कमी होने से आपको एनीमिया होने का जोखिम बढ़ सकता है. आयरन रिच डाइट आज से लेना शुरू कर दें.

6. ओमेगा-3 फैटी एसिड्स

माना जाता है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड्स कॉग्निशन और हार्ट की सेहत में सुधार करते हैं. ये लाभकारी फैट शरीर के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को भी सामान्य और नियंत्रित करते हैं. तो आप यदि 40 की हो चुकी हैं तो बेहद जरूरी है कि आप ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स का सेवन करें.

महिलाओं और बेटियों को होगा तगड़ा मुनाफा, जानिए कैसे कैलकुलेट होता है रिटर्न

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 24 के लिए पेश किए गए बजट भाषण में महिला सम्मान सेविंग स्कीम के घोषणा की थी। इसके तहत सरकार देश की महिलाओं और बेटियों को एक सुरक्षित निवेश करने का विकल्प प्रदान करती है।

देश में महिलाओं के लिए सरकार महिला सम्मान बचत योजना चला रही है। भारत की कोई भी महिला और बेटी इस एकमुश्त योजना को अपने नाम से खोलवा सकती है। इस योजना को 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लड़कियों सहित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पेश किया गया था।

महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र केवल बालिका या महिला के नाम पर ही बनवाया जा सकता है। इस योजना पर अर्जित ब्याज का भुगतान मैच्यौरिटी पर किया जाता है हालांकि ब्याज हर त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है।

महिला बचत योजना पर कैसे कैलकुलेट होता है रिटर्न?

इस योजना के लिए निवेश पर रिटर्न की गणना एक सिंपल इंटरेस्ट रेट के सूत्र का उपयोग करके की जाती है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र पर रिटर्न की गणना साप्ताहिक रूप से की जाती है और निवेश किए गए पैसों की, संचयी फिक्स्ड डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट प्रोग्राम के समान चक्रवृद्धि की जाती है।

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आप इस योजना में 2 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं तो आपको पहली तिमाही के बाद 3,750 रुपये का ब्याज मिलेगा। दूसरी तिमाही के अंत में इस राशि का पुनर्निवेश करने पर आपको 3,820 रुपये का ब्याज मिलेगा। बांड के परिपक्व होने पर आपको 2,32,044 रुपये मिलेंगे।

कितना मिलता है इंटरेस्ट रेट?

आपको बता दें कि 2023 से 2025 के बीच महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र दो साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। इन दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर मिलता है।

ब्याज पर कटेगा TDS

CBDT की और से एक महीने पहले यानी 16 मई 2023 को जारी एक अधिसूचना में जानकारी दी थी कि योजना से अर्जित ब्याज पर कोई टैक्स छूट नहीं दिया जाएगा। आयकर की धारा 194A के तहत टीडीएस तब लागू होता है जब एक वित्तीय वर्ष में योजना से अर्जित ब्याज 40,000 रुपये से अधिक हो।

योजना में किसे करना चाहिए निवेश?

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र में देश की महिलाओं और बेटियों को उम्र और बिजनेस की परवाह किए बिना सभी को निवेश करना चाहिए।

चूंकी यह योजना सरकारी गारंटी के साथ आती है इसलिए इसमें जोखिम कम है। इस प्रमाणपत्र में निवेश करके महिलाएं सरकार समर्थित योजना का लाभ उठाते हुए अपनी बचत पर एक निश्चित रिटर्न कमा सकती हैं।

मतदाताओं को लुभाने वाला लॉलीपॉप भारी पड़ा, कांग्रेस के बाद आप सरकार से एक हजार रुपये मांगने पहुंची महिलाएं

परिवहन विशेष न्यूज

आम चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्येक माह मतदाताओं के खाते में नगद डालने का लॉलीपॉप अब उनपर ही भारी पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भरवाए गए गारंटी कार्ड लेकर जहां लखनऊ के साथ ही विभिन्न राज्यों के पार्टी दफ्तरों पर भारी संख्या में महिलाओं का जुटने का क्रम जारी है जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं है।

नईदिल्ली। आम चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्येक माह मतदाताओं के खाते में नगद डालने का लॉलीपॉप अब उनपर ही भारी पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भरवाए गए गारंटी कार्ड लेकर जहां लखनऊ के साथ ही विभिन्न राज्यों के पार्टी दफ्तरों पर भारी संख्या में महिलाओं का जुटने का क्रम जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं है।

अब इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) का घेराव भी शुरू हो गया है। मंगलवार को दिल्ली महिला मंच के बैनर तले सैकडों महिलाएं राज्य की वित्त मंत्री आतिशी के सरकारी निवास पर इकट्ठा होकर उनसे जल्द राशि का भुगतान शुरू करने की मांग की।

इंडिया गेट पर भी पहुंचीं

ये सभी पहले इंडिया गेट पर इकट्ठा हुईं और मथुरा रोड स्थित आतिशी के सरकारी आवास के नजदीक पहुंच गई। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को रोक लिया।

दिल्ली सरकार से पूछे सवाल

महिलाओं का नेतृत्व कर रहीं मीना खन्ना, रूचि अग्रवाल, शाजिया खान, गजाला इमरान व साफिया फहीम समेत अन्य महिलाएं हाथ में "दिल्ली की बेटियों का एक सवाल- कब मिले प्रति माह एक हजार" दिल्ली की महिला करेंगी हिसाब-अब मत भागो दिल्ली की झूठी सरकार" जैसे नारे लिखे प्लेकार्ड हाथ में लिखी हुई थी तथा दिल्ली सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगा रही थी।

एक हजार रुपये देने का किया था वादा

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये देने की घोषणा की। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गरीब महिलाओं से इंटरनेट आधारित फार्म भरवाए गए। अब चुनाव बाद पूरी सरकार और उसके विधायक महिलाओं से छुप रहे हैं।

आक्रोशित महिलाओं ने दिल्ली सरकार पर जनता को गुमराह कर वोट लेने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि अगले माह से उन्हें भुगतान शुरू नहीं होता तो वे सभी आप विधायकों का भी घेराव करेंगी।

कटघरे में डर्टी>नीट, सुप्रीमकोर्ट ने कांऊंसिलिंग पर रोक लगाने से किया इंन्कार

परिवहन विशेष।एसडी सेठी।

नई दिल्ली। देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुपर एग्जाम कहलाने वाले नीट के एग्जाम को सवालों के कटघरे में खडा कर दिया है। इससे इस एग्जाम में बैठने वाले लाखो स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड हो गया है।

नीट एग्जाम के रिजल्ट में व्रती गई धांधलियों को लेकर स्टूडेंट्स ने जब न्याय के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने कांऊंसिलिंग तक पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।इन हालातों में सवालों में घिरे नीट एग्जाम बॉडी ने अपने दामन को पाक साफ बता कर पल्ला झाड लिया है। अब ऐसी सूरत में नीट बॉडी ने स्टूडेंट्स के लिए सूइसाइड का रास्ता खोल दिया है। उल्लेखनीय है कि नीट एग्जाम के परिणाम में 67 कैंडिडेट्स को एक साथ 720 में 720 अंक कैसे प्राप्त हुए? सभी का आल इंडिया रैंक नंबर 1 आया है। इस बावत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो जवाब दिए है वह गले नहीं उतर रहे हैं। एनटीए का कहना है कि जिन 67 स्टूडेंट्स को 720 /720 अंक मिले हैं,उन सभी को टॉपर नहीं माना जाएगा।दरअसल 67 में से 44 स्टूडेंट्स को आंसर की में बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले है। इस वजह से इन स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर

किया है। वहीं सवाल नं-2 में 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए ? इसके जवाब में बताया गया है कि एग्जाम में कैमिस्ट्री के सेक्शन में एटम से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। आंध्र आंध्र की आप्शन में 1 सही था। जबकि पुरानी एनसीईआरटी किताब के हिसाब से आप्शन -3 सही था।ऑप्शन-3 टिक करने वालों को बोनस नंबर मिले हैं।

अब सवाल उठता है कि एक ही एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट्स को आल इंडिया रेंक नंबर-1 कैसे मिली? इसके जवाब में एग्जाम टेस्टिंग एजेंसी का कहना है किये केवल संयोग हुआ है। एटीए की सफाई को स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं है।लेकिन स्टूडेंट्स मांग है कि फा इन निर्णय आने तक कम से कम कांऊंसिलिंग पर तो रोक लगा देनी चाहिए। स्टूडेंट्स की इस याचिका को भी सुप्रीमकोर्ट ने मानने से इन्कार कर दिया है। अब स्टूडेंट्स की मांग को लेकर विपक्ष की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी नीट परिणाम पर गडबडी के आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने 8 जून को लोकसभा को पत्र लिखकरणनीट-2024 की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं राहुल गांधी ने 9 जून को एक्स पर लिखा था कि शिक्षा माफिया से निपटना बेहद जरूरी है।इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परीक्षा में अपने को ठगा महसूस करने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कहा कि नीट एग्जाम में हुई धांधली ने 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड दिया है।राहुल गांधी ने लिखा कि शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से चल रहे इस पेपर लीक उधोग से निपटने के लिए ही कांग्रेस ने एक रॉबर्ट प्लान बनाया था।हमने अपने मैनिफेस्टो में कानून बना कर छात्रों को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। वहीं देश के सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाया है कि वह संसद में स्टूडेंट्स की आवाज बन कर स्टूडेंट्स से जुडे हुए मुद्दो को मजबूती से उठाऊंगा।

दिल्ली में जल संकट के बीच अब भाजपा ने आप पर लगाया 'पानी चोरी' करने का आरोप

राजधानी में जल सकंट पर दिल्ली और हरियाणा आमने-सामने हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर टैंकरों से पानी चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। इससे पहले जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा की नायब सैनी सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से हरियाणा सरकार मुनक नहर में पानी कम छोड़ रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के मंत्री बार-बार झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा (Haryana News) से दिल्ली को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण दिल्ली में पानी की समस्या हो रही है। सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार द्वारा उत्पन्न किया हुआ यह जल संकट है।

हरियाणा से दिल्ली को मिल रहा अधिक पानी-सचदेवा: प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा, नौ जून को दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों ने मुनक नहर उससे दिल्ली तक आने वाले पानी निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने यह माना था कि हरियाणा से दिल्ली को अधिक पानी मिल रहा है। मुनक से काकोरी आते-आते 20 प्रतिशत पानी बर्बाद या चोरी हो रहा है। उन्होंने सड़क पर खड़े टैंकरों की तस्वीर जारी की।

अवैध रूप से खड़े टैंकर से होती है पानी की चोरी-भाजपा नेता: दावा किया कि तस्वरी काकोरी से पहले की है और अवैध रूप से खड़े टैंकर से पानी की चोरी होती है। जल मंत्री आतिशी को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जल बोर्ड के अधिकारियों की तैनाती के बाद भी कैसे पानी चोरी की जा रही है। उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी कर दावा किया किया बीआरटी कोरिडोर के नजदीक से लगभग साढ़े तीन किलोमीटर के हिस्से में 80 स्थानों पर रिसाव होने से पानी की बर्बादी हो रही है।

पानी की चोरी व बर्बादी से दिल्ली में जल संकट-भाजपा: पानी की चोरी व बर्बादी से दिल्ली में जल संकट है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त जल मिलने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि, न तो दिल्ली जल बोर्ड के पास इसे शोधित करने की व्यवस्था है और न संग्रहण की।

200 कांवड़ शिविर लगाएगी केजरीवाल सरकार, वाटर प्रूफ टेंट; मेडिकल और पानी समेत होगी ये तमाम सुविधाएं

दिल्ली में कांवड़ियों की सुविधा के लिए इस साल आम आदमी पार्टी सरकार पूरी दिल्ली में करीब 200 कांवड़ शिविर लगाने जा रही है। जिसमें सबसे ज्यादा पूर्वी दिल्ली उत्तरी पूर्वी दिल्ली एवं शाहदरा जिले में लगाया जाएगा। राजस्व मंत्री आतिशी ने आज सभी जिलों के डीएम और विभाग के उच्चाधिकारियों के संग तैयारियों को लेकर बैठक की।

नई दिल्ली। कांवड़ियों की सुविधा के लिए इस साल आप सरकार पूरी दिल्ली में करीब 200 कांवड़ शिविर लगाएगी। पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली एवं शाहदरा जिले दिल्ली में कांवड़ियों के एंट्री प्वाइंट है। ऐसे में इन तीनों जिलों में सबसे ज्यादा शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी ज़िलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अभी से लेकर शिविर के आयोजन तक हर ज़िलाधिकारी हर सप्ताह तैयारियों से जुड़ी रिपोर्ट उनको सौंपे।

राजस्व मंत्री आतिशी (Atishi News) मंगलवार को सभी ज़िलों के डीएम और विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ कांवड़ शिविर की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि कांवड़ियों के लिए शिविरों में वाटर प्रूफ टेंट, फर्नीचर, शौचालय, पानी, मेडिकल सहित अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सभी जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए कि कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं के लिए हर जरूरी कदम सुनिश्चित उठाया जाए।

राजस्व मंत्री ने कहा कि सावन के इस पवित्र महीने में केजरीवाल सरकार शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा, सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार हर जरूरी इंतजाम कर रही है।सभी जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए है ताकि कहीं किसी प्रकार की समस्या का सामना उत्पन्न न हो।

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए स्थानीय डिस्पेंसरियों को शिविरों से जोड़ा जाएगा। किसी भी आपातक़ालीन स्थिति के लिए कैट्स एंबुलेंस की उपलब्धता होगी। साथ ही अस्पतालों को कांवड़ियों के इलाज के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए जाएंगे।

संविधान और लोकतंत्र बचाने में मुसलमानों की अहम भूमिका

ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत (पंजीकृत) की जनरल बॉडी बैठक, डॉ. जफरुल इस्लाम खान चुने गये अध्यक्ष

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधि संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत (पंजीकृत) की जनरल बॉडी की बैठक पिछले रविवार को न्यू होराइजन स्कूल, हज़रत निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें देश भर से प्रमुख सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए। । इस बैठक के दौरान डॉ. जफरुल इस्लाम खान को सर्वसम्मति से दो वर्षों के लिए मुशावरत का अध्यक्ष चुना गया और उन्हें आपसी परामर्श से मुशावरत का संविधान तैयार करने का अधिकार दिया गया, जिसे अगली जनरल बॉडी की बैठक में अनुमोदित किया जाएगा।

इस बैठक के दौरान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई और जो प्रस्ताव पारित किए गए, उनमें कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत की जनरल बॉडी पिछले आम चुनावों के नतीजों पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए मतदाताओं को बधाई देती है जिन्होंने नफरत की राजनीती करने वालों को अस्वीकार कर दिया। इन नतीजों से यह स्पष्ट है कि देश में अभी भी धर्मनिरपेक्ष लोगों का बहुमत है और संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है, इसलिए चुनावों के दौरान मुसलमानों ने देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसलिए सेकुलर पार्टियां मुसलमानों की समस्याओं के बारे में अपना वाज़ेह मौकफ अख्तियार करें।

प्रस्ताव में कहा गया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद नफरत फैलाने वालों को केवल चालीस फीसदी वोट मिले हैं और साठ फीसदी मतदाताओं ने नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है।

ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत (पंजीकृत) ने इस अवसर पर धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने छोटे-मोटे मतभेदों को भुलाकर देश के व्यापक हितों के लिए अपनी एकता स्थापित करें और देश को वास्तविक लोकतंत्र में वापस लाएं। एक दूसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि मुशावरत मुसलमानों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग करने के एजेंडे की निंदा करती है और मुसलमानों को सलाह देती है कि वे राष्ट्रहित में नफरत की राजनीति को सफल न होने दें।

मुशावरत पिछले दस वर्षों में मुसलमानों को राजनीतिक रूप से निरस्त करने और हाशिए पर धकेलने के प्रयासों

की निंदा करती है। गो हत्या, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन आदि जैसे काल्पनिक मुद्दे खड़ा करके उनकी मोबलिंचिंग हुई है, जिसे मुसलमानों ने धैर्यपूर्वक सहन किया है और जवाबी कार्रवाई से परहेज किया है ताकि प्रशासनिक मशीनरी को मुसलमानों पर और अधिक अत्याचार करने का मौका न मिले। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, मुसलमानों को अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने, कुरान से जुड़ने के साथ साथ आवश्यक सभी संसाधनों को अपनाएं जो कौमों के भौतिक विकास के लिए आवश्यक हैं।

जिसमें शैक्षिक विकास और व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है ।

मुशावरत ने मुसलमानों से बढ़ते उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी तरीके अपनाने और न्याय मिलने तक कानूनी संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करने और पीड़ितों के परिवारों का समर्थन करने का आग्रह किया है।

जनरल बॉडी की बैठक में गजा में चल रहे इजराइली नरसंहार की निंदा के अलावा इस मामले में मुस्लिम देशों की आपराधिक चुप्पी की भी निंदा की गई,

मुशावरत ने देश के इंसाफ़ पसंद अवाम से अपील की है कि इस नरसंहार एवं फिलिस्तीन पर सालों से जारी इजराइली कब्जे की निंदा करें. प्रस्ताव में कहा गया है कि मध्य पूर्व में संकट का अंत तभी संभव है जब फिलिस्तीनियों को अपने देश में स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वायत्तता के साथ रहने का अवसर मिलेगा। भारत सरकार से कहा गया है कि गजा में नरसंहार को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करे। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों की भूमिका की भी सराहना की गई है। बैठक के महत्वपूर्ण प्रतिभागियों में राज्यसभा के पूर्व सदस्य मुहम्मद अदीब, अब्दुल खालिक (पूर्व सांसद असम), ख्वाजा मुहम्मद शाहिद, डॉ. बसीर अहमद खान, अब्दुल अजीज (कलकत्ता), सुश्री उज़्मा नाहिद (मुंबई), डॉ. जफरुल इस्लाम खान, मुफ्ती अताउर रहमान कासमी, प्रो. मुहम्मद सुलेमान (कानपुर), कमाल फारूकी, मुहम्मद वजीर अंसारी (आईपीएस सेवानिवृत्त), डॉ. सैयद मेहरुल हसन (भोपाल), काजी जैनुसाजेदीन (शहर काजी मेरठ), प्रो. अर्शी खान (अली गढ़), डॉ. कौसर उस्मान, एडवोकेट नदीम सिद्दीकी (लखनऊ), हसीब अहमद (पूर्व सदस्य सचिव एनसीटीई), अब्दुल बातन खांडिकर (एमएलए असम), शबीह अहमद, मुहम्मद नदीम सिद्दीकी, अबरार अहमद मक्की, शाहिद शरीफ शेख, अखलाक हुसैन चिश्ती, हाफिज मंजूर अली खान, मुहम्मद इकबाल अल-जफर, सऊदुल हसन नदवी (गाजीपुर), एडवोकेट सिकंदर हयात खान, मुहम्मद जमीलुर रहमान (सदस्य विधानसभा मालिरकोटला), मासूम मुरादाबादी, सैयद तहसीन अहमद, मुहम्मद शमसुज़्ज़ुहा, डॉ. सैयद अहमद खान, फ़िरोज़ खान गाज़ी एडवोकेट, सोहेल अंजुम और डॉ. जावेद अहमद उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा कई सदस्य ज़ूम के ज़रिए भी इस मीटिंग से जुड़े।

राष्ट्रपति ने मंजूर किया मंत्री राज कुमार आनंद का इस्तीफा, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर AAP छोड़ बसपा में हुए शामिल

राज कुमार आनंद का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर 31 मई को आनंद के इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए। राजुकमार आनंद ने 10 अप्रैल को अपना इस्तीफा दिया। चूंकि सीएम केजरीवाल जेल में थे ऐसे में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। केजरीवाल ने जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद इस पर हस्ताक्षर कर दिया।

नई दिल्ली। राज कुमार आनंद का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर 31 मई को आनंद के इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए। राजुकमार आनंद ने 10 अप्रैल को अपना इस्तीफा दिया था। चूंकि सीएम केजरीवाल जेल में थे, ऐसे में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। केजरीवाल ने जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद इस पर हस्ताक्षर कर दिया। 3 जून को एलजी ने उनका इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया था। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद से इस्तीफा देते समय आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई है अब मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता। बता दें कि वह दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। राजकुमार आनंद के घर ईडी ने छापेमारी की थी। पार्टी ने तब कहा था कि वह ईडी की रेड से डरकर पार्टी छोड़ी है।

बसपा से लड़ा था चुनाव: नई दिल्ली लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर राजकुमार आनंद चुनावी मैदान में थे। इस सीट पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज और आप के सोमनाथ भारती भी एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। राज कुमार आनंद तीसरे नंबर पर रहे थे।

गुरुग्राम के मकान में लगी AC ने पकड़ी भीषण आग, पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से पाया काबू

गुरुग्राम जिले (Gurugram Fire) के बादशाहपुर के सुशांत लोक फेस दो के सी ब्लॉक में एसी में आग लगने से मकान में भयंकर आग लग गई। समय पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से बड़ा हादसा होने से टला। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। आग लगने से मकान में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है।

बादशाहपुर (गुरुग्राम)। सुशांत लोक फेस दो के सी ब्लॉक में एसी में आग लगने से मकान में आग लग गई। पर्दों में आग लगती देख पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से बड़ा हादसा बच गया। मकान में लगे पर्दे और अन्य सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। सुशांत लोक दो और तीन आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि सी ब्लाक में एसी में आग लगने के कारण एक मकान में आग लग गई। आग लगने के बाद लोगों ने 112 पर पुलिस को सूचना दी। तुरंत सेक्टर-56 थाना प्रभारी और पुलिस (Gurugram Police) मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां भी तुरंत मौके पर पहुंची। आग लगने से मकान में कुछ नुकसान हुआ है। पर आग पर जल्दी काबू पाए जाने से बड़ा हादसा बच गया।

इसी माह होगा नोएडा फिल्म सिटी का शिलान्यास, तीन साल में फिल्म सिटी का निर्माण कर संचालन शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

फिल्म सिटी का शिलान्यास इसी माह 22 से 24 तारीख के बीच होगा। एक हजार एकड़ में विकसित होने वाली फिल्म सिटी परियोजना का पहला चरण 230 एकड़ का है। यमुना प्राधिकरण सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि बोनी कपूर इसी माह 22 से 24 जून के दौरान ग्रेटर नोएडा आएंगे। फिल्म सिटी को सात जोन में पूरा किया जाना है।

ग्रेटर नोएडा। फिल्म सिटी का शिलान्यास इसी माह 22 से 24 तारीख के बीच होगा। इससे पहले यमुना प्राधिकरण फिल्म सिटी की विकासकर्ता कंपनी बेव्यू को जमीन पर कब्जा देगा। फिल्म सिटी के लिए गठित एसपीवी में प्राधिकरण के सीईओ एवं एक एसीईओ बतौर निदेशक शामिल होंगे। यह कंपनी फिल्म सिटी के विकास और संचालन के लिए जिम्मेदार होगी।

फिल्म सिटी परियोजना का पहला चरण 230 एकड़ का

उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी यीडा के सेक्टर 21 में विकसित करने के लिए फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर व भूटानी समूह की कंपनी बेव्यू को विकासकर्ता चयन किया गया था। कंपनी ने 18 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी की बोली लगाकर फिल्म सिटी की निविदा हासिल की थी। एक हजार एकड़ में विकसित होने वाली फिल्म सिटी परियोजना का पहला चरण 230 एकड़ का है। इसके लिए बेव्यू कंपनी का चयन किया गया है।

बोनी कपूर इसी माह 22 से 24 जून के दौरान आएंगे ग्रेटर नोएडा

यमुना प्राधिकरण सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि बोनी कपूर इसी माह 22 से 24 जून के दौरान ग्रेटर नोएडा आएंगे। तभी जमीन पर कब्जा देने व फिल्म सिटी के शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। प्राधिकरण व बेव्यू कंपनी के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अनुसार ही फिल्म सिटी का विकास और संचालन होगा। विकासकर्ता को एसपीवी के गठन एवं बैंक गारंटी के पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं।

फिल्म सिटी को सात जोन में किया जाएगा विकसित

यमुना प्राधिकरण ने बेव्यू कंपनी को फिल्म सिटी के लिए विकास एवं संचालन का 90 साल का लाइसेंस दिया है। नौवें साल से प्राधिकरण को फिल्म सिटी के ग्रौस राजस्व में 18 प्रतिशत ही हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो जाएगी। तीन साल में फिल्म सिटी का निर्माण कर संचालन शुरू हो जाएगा। फिल्म सिटी को सात जोन में विकसित किया जाएगा। इसमें प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन की सुविधा होगी।

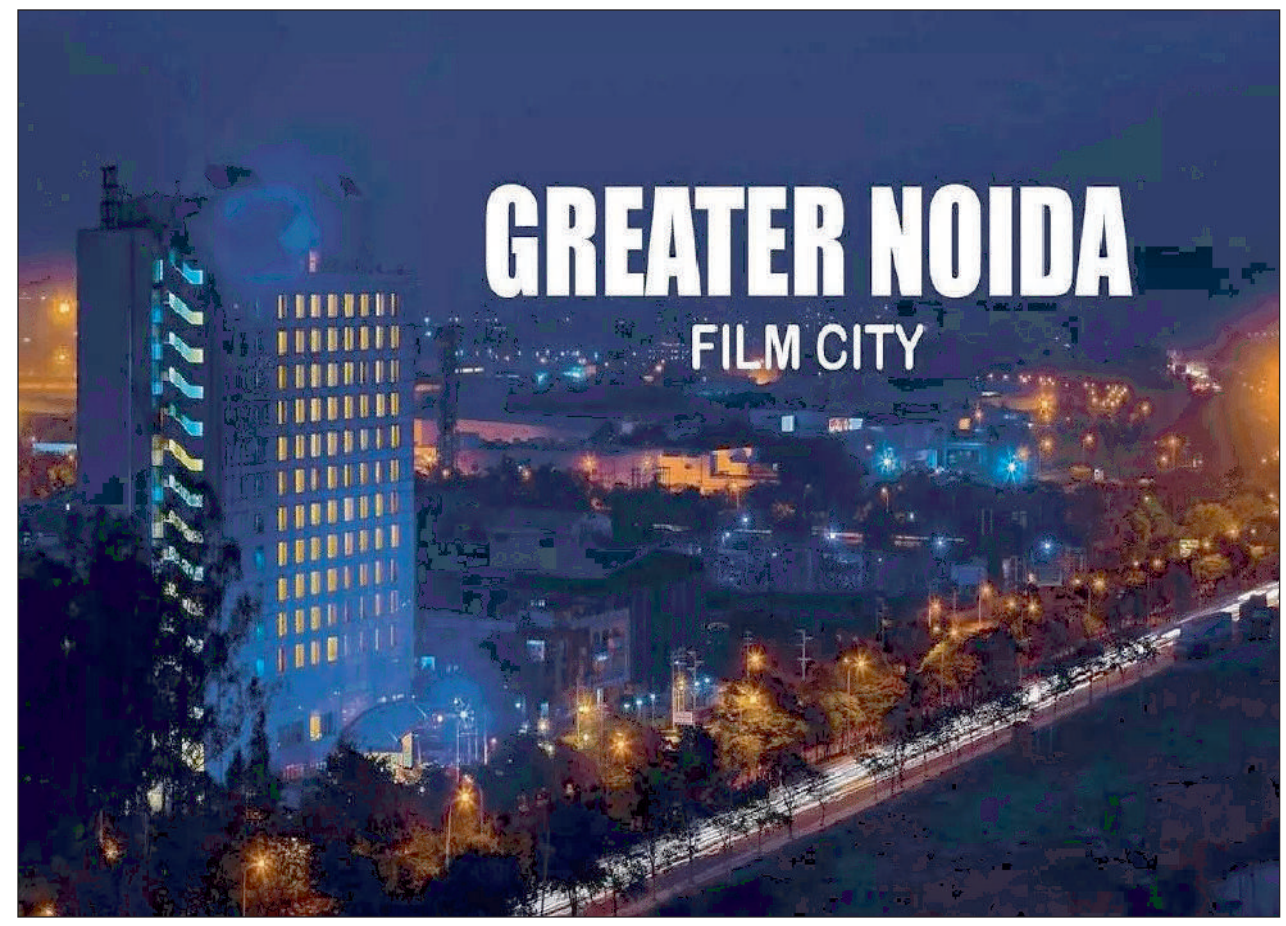

दिनदहाड़े सर्राफ को मारी गोली, बदमाशों ने लाखों का सोना-चांदी और नकदी लूटी

परिवहन विशेष न्यूज

नंदग्राम पुलिस चौकी के पास बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली से आए आभूषण कारोबारी को शाम पांच बजे गोली मारकर सोना पांच किलो चांदी और करीब डेढ़ लाख रुपये नकदी लूट ली। सिहानी निवासी अंकित वर्मा अपने छोटे भाई दीपक वर्मा के साथ हिंडन विहार में आभूषण की दुकान करते हैं। मंगलवार को दोनों भाई दिल्ली माल लेने गए थे।

गाजियाबाद। नंदग्राम पुलिस चौकी के पास बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली से आए आभूषण कारोबारी को शाम पांच बजे गोली मारकर सोना, पांच किलो चांदी और करीब डेढ़ लाख रुपये नकदी लूट ली। सिहानी निवासी अंकित वर्मा अपने छोटे भाई दीपक वर्मा के साथ हिंडन विहार में आभूषण की दुकान करते हैं। मंगलवार को दोनों भाई दिल्ली माल लेने गए थे। वापसी में दोनों बाइक पर जब राजनगर एक्सटेंशन पुलिस चौकी के पास पहुंचे तो उन्हें पीछे से एक बाइक पर आए दो बदमाशों ने ओवरटेक कर रोका और थैला छीनने का प्रयास किया। दोनों भाइयों ने विरोध किया तो बदमाशों ने हाथापाई शुरू कर दी। इसी बीच दीपक ने एक बदमाश के हेलमेट मार दिया। बदमाश ने पिस्टल से दीपक के गोली मारी और दोनों भाइयों से थैला लूटकर ले गए। थैले में करीब साढ़े सात लाख रुपये का 100 ग्राम सोना, डेढ़ लाख रुपये नकद और पांच किलो चांदी थी। दोनों भाइयों ने तत्काल पुलिस को फोन करने के साथ ही पुलिस चौकी पर घटना की सूचना दी। दीपक को जीटीबी अस्पताल भर्ती कराया गया है। दीपक की बाजू में गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश की जा रही है।

मैक्स अस्पताल में इलाज कराने आई उज्बेकिस्तान की महिला ने किया सुसाइड, बाथरूम में इस हालत में मिला शव

साहिबाबाद के कौशांबी थाना इलाके में वैशाली सेक्टर में मौजूद मैक्स अस्पताल में इलाज कराने आई उज्बेकिस्तान की 45 साल की महिला ने आज सुसाइड करके आत्म हत्या कर ली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

साहिबाबाद। कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर एक स्थित मैक्स अस्पताल में इलाज कराने आई उज्बेगिस्तान की 45 वर्षीय महिला ने मंगलवार को बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक उज्बेगिस्तान की 45 वर्षीय जुल्फिया लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए भारत आई थीं। 25 मई को जुल्फिया का लिवर ट्रांसप्लांट हो गया। वह पति खैरुला के साथ यहीं अस्पताल में थीं। मंगलवार दोपहर को जुल्फिया बाथरूम गईं। काफी देर होने के बाद भी जब वह बाहर नहीं आईं तो खैरुला ने सुरक्षा गार्ड और हाउस कीपिंग स्टाफ को इसकी जानकारी दी।

'गाजियाबाद में 90 के दशक के कश्मीर जैसे हालात', भाजपा के इस विधायक ने क्यों कही ये बात

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ आज चौथा पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने दावा किया कि जिले में 90 के दशक के कश्मीर जैसे हालात बने हुए हैं। यूपी के शासन में अपर मुख्य सचिव को लिखे अपने इस पत्र में नंद किशोर ने कहा कि यहां पर कानून व्यवस्था बद से बदतर है।

गाजियाबाद। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मंगलवार को चौथा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है 90 के दशक में कश्मीर में जो हालात थे, वैसे हालात अब गाजियाबाद में बन गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव गृह को भेजे पत्र में विधायक ने बताया कि गाजियाबाद में कानून व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है। भाजपा के प्रदेश मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति बसंत त्यागी भी सुरक्षित नहीं हैं।

फोन पर दो बार जान से मारने की दी जा चुकी धमकी-BJP विधायक

उनको फोन पर दो बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। लेकिन दोषियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जिले में जब भाजपा (UP BJP) के नेता ही सुरक्षित नहीं हैं तो आमजन की क्या स्थिति होगी। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति से वह पहले ही अवगत करा चुके हैं।

आज सराफा व्यापारी को गोली मारकर 13 लाख रुपये लूटे

लेकिन पुलिस (Ghaziabad Police) की कार्यशैली से ऐसा प्रतीत होता है कि जिले में आम जनता तो छोड़िए विधायक और भाजपा नेताओं की हत्या कराने पर पुलिस आयुक्त तुले हैं। मंगलवार को नंदग्राम में सराफा व्यापारी को गोली मारकर 13 लाख रुपये के कैश और जेवर लूट लिए गए।

तीन दिन में दोषियों को गिरफ्तार कर हो कार्रवाई-नंद किशोर गुर्जर

रोजाना आपराधिक वारदातें हो रही हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने बसंत त्यागी को सुरक्षा उपलब्ध कराने और तीन दिन में दोषियों को गिरफ्तार कर कठोरतम कार्रवाई की मांग की है।

संघ प्रमुख भागवत ने भाजपा और मोदी को खरी खरी सुना कर क्या संदेश दिया है?

नीरज कुमार दुबे

आरएसएस प्रमुख ने अपने संबोधन के जरिये जिस तरह के तेवर दिखाये हैं उससे प्रदर्शित हो रहा है कि इस बार स्पष्ट बहुमत से दूर रही भाजपा को सिर्फ अपने गठबंधन सहयोगियों को ही साथ लेकर नहीं चलना होगा बल्कि संघ परिवार के लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा।

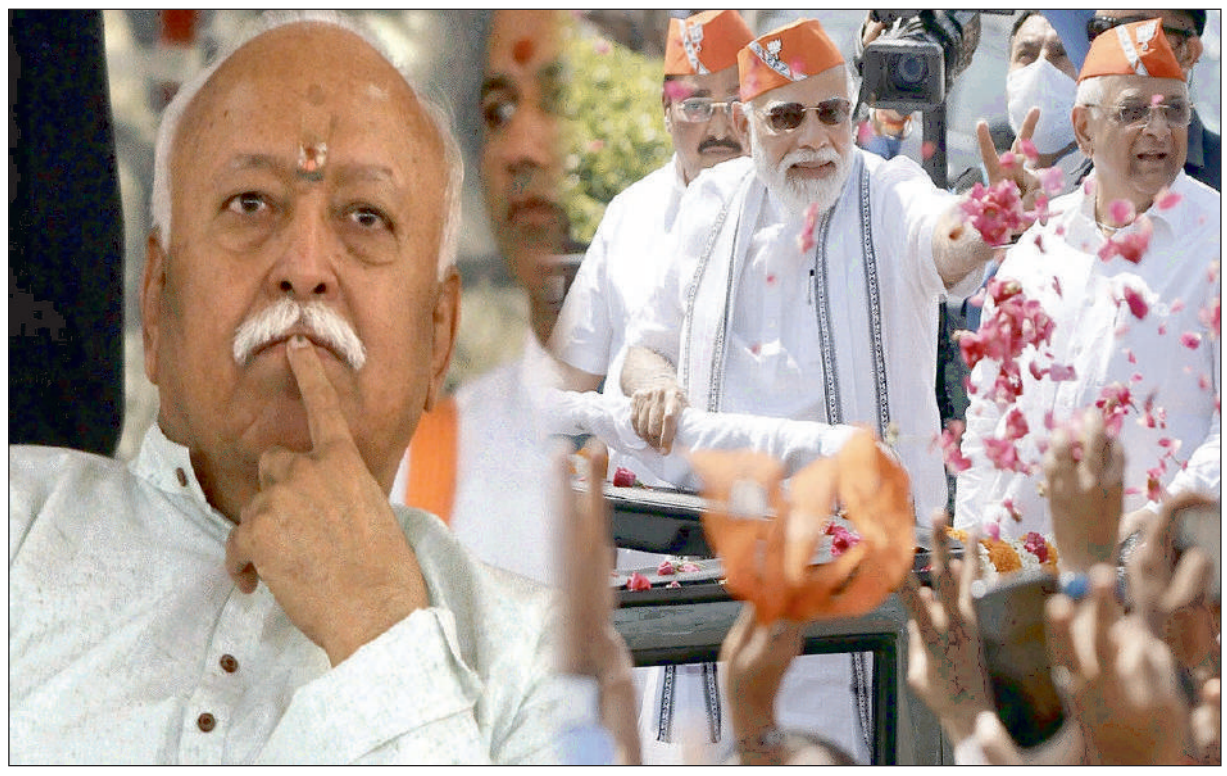

नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो देश-दुनिया से बधाई संदेश आने लगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने इसी बीच मोदी सरकार और भाजपा को जिस तरह खरी-खरी सुनाई उससे सब आश्चर्यचकित हैं। हालांकि विपक्ष ने भागवत की टिप्पणियों का स्वागत किया है। देखा जाये तो मणिपुर की अशांति को लेकर भाजपा की चुप्पी पर मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है वह एनडीए सरकार के लिए बड़ी चेतावनी की तरह है। मणिपुर में अब भी जिस तरह से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वहां के मुद्दे हल करने में केंद्र और राज्य सरकार नाकाम रही हैं।

इसके अलावा, आरएसएस प्रमुख ने अपने संबोधन के जरिये जिस तरह के तेवर दिखाये हैं उससे प्रदर्शित हो रहा है कि इस बार स्पष्ट बहुमत से दूर रही भाजपा को सिर्फ अपने गठबंधन सहयोगियों को ही साथ लेकर नहीं चलना होगा बल्कि संघ परिवार के लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा। आरएसएस के कई पदाधिकारी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि चुनावों से पहले भाजपा ने अति आत्मविश्वास के साथ 'अबकी बार 400 पार' का नारा लगाना शुरू किया था तब संघ परिवार के लोगों ने उन्हें जमीन पर रह कर काम करने की सलाह दी थी लेकिन पार्टी के नेताओं को 'मोदी है तो मुमकिन है' नारे पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी और आखिरकार मुंह की खानी पड़ी। देखा जाये तो लगभग ऐसी ही स्थिति साल 2004 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी हुई थी जब भाजपा के नेता इंडिया शाइनिंग के नारे पर इतना भरोसा कर रहे थे कि उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दी थी। रही सही कसर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कथित तौर पर आरएसएस के बारे में दिये गये बयान से पूरी हो गयी थी। चुनावों के बीच ही आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह भाजपा से दूरी बना ली थी उससे पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह इशारों इशारों में भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाये हैं उससे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा के नये अध्यक्ष के चयन में अब नागपुर की ज्यादा चलेगी। हम आपको याद दिला दें कि 2009 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की हार के बाद भागवत की पहल पर ही नितिन गडकरी को नागपुर से दिल्ली भेजा गया था ताकि वह पार्टी को संभालें। उस समय भाजपा में लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार जैसे नेता दिल्ली की राजनीति में प्रभावी थे लेकिन सबको दरकिनार कर गडकरी को लाया गया था।

जहां तक मोहन भागवत के संबोधन की बात है तो आपको बता दें कि एक तो उन्होंने मणिपुर में एक वर्ष बाद भी शांति स्थापित नहीं होने पर चिंता जताई है साथ ही देश के सभी समुदायों के बीच एकता पर जोर दिया है। आरएसएस प्रमुख ने साथ ही चुनावी बयानबाजी से बाहर आकर देश के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अपनी पहली टिप्पणी में भागवत ने कहा है कि नतीजे आ चुके हैं और सरकार बन चुकी है, इसलिए क्या और कैसे हुआ आदि पर अनावश्यक चर्चा से बचना चाहिए। भाजपा की सीटें घटने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस ''कैसे हुआ, क्या हुआ'' जैसी चर्चाओं में शामिल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि संगठन केवल मतदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का अपना कर्तव्य निभाता है।

इसके अलावा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के संबंधों में जिस तरह की खटास हाल के वर्षों में देखने को मिली है उस ओर इशारा करते हुए भागवत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि आम जनता के लिए काम किया जा सके। भागवत ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव बहुमत हासिल करने के लिए होते हैं और यह एक प्रतिस्पर्धा है, युद्ध नहीं। उन्होंने विपक्ष को विरोधी कहने की बजाय प्रतिपक्ष नाम से पुकारने का सुझाव भी दिया है। भागवत का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल और नेता एक-दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इससे समुदायों के बीच दरार पैदा हो सकती है। भागवत का इस बात पर अफसोस जताना भी स्वाभाविक ही था कि आरएसएस को बिना किसी कारण राजनीतिक विवादों में घसीटा जाता है।

दूसरी ओर, भले इस बार का लोकसभा चुनाव बिना किसी विघ्न के संपन्न हुआ लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में मिथ्या प्रचार और अफवाहों का बाजार खूब देखने को मिला। इस ओर भी इशारा करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि चुनाव में हमेशा दो पक्ष होते हैं, लेकिन जीतने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने परोक्ष तौर पर डीपफेक आदि की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि तकनीक का उपयोग करके झूठ फैलाया गया। हम आपको याद दिला दें कि चुनावों के बीच ही गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण के बारे में विवादित बयान वाला डीपफेक वीडियो जारी किया गया था जिसे कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा भी कर दिया था।

इसके अलावा, भागवत ने देश की विविधता का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की नसीहत देते हुए यह भी कहा कि एक दूसरे की उपासना पद्धति का सम्मान किया जाना चाहिए। भागवत का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि इस्लाम और ईसाई जैसे धर्मों की अच्छाई और मानवता को अपनाया जाना चाहिए और सभी धर्मों के अनुयायियों को एक-दूसरे का भाई-बहन के रूप में सम्मान करना चाहिए। देखा जाये तो भागवत की यह नसीहत उन लोगों के लिए खासतौर पर है जो टीवी की बहसों और सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों में धर्म विशेष को निशाना बनाते हैं। यकीनन ऐसे लोगों के चलते ही समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ता है।

इसके अलावा, जो लोग बात-बात पर दूसरों को देश छोड़कर कहीं ओर बस जाने की सलाह देते हैं, उनकी ओर इशारा करते हुए भागवत ने कहा है कि सभी को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि यह देश हमारा है और इस भूमि पर जन्म लेने वाले सभी लोग हमारे अपने हैं। आरएसएस प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया है कि कुछ लोगों की यह सोच कि केवल विदेशी विचारधाराएं ही सत्य हैं, समाप्त होनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अतीत की बातों को भूलने और सबको अपनाने की सीख दी है। साथ ही उन्होंने जातिवाद को पूरी तरह से खत्म करने का आह्वान करते हुए अपने संगठन के पदाधिकारियों से समाज में सामाजिक सद्भाव की दिशा में काम करने के लिए कहा है।

बहरहाल, संघ प्रमुख के नागपुर में दिये गये संबोधन को लेकर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वह दर्शा रही हैं कि प्रतिपक्ष को भाजपा पर वार करने के लिए नया हथियार मिल गया है। खैर...पहले ही चुनावी नतीजों से परेशान दिख रही भाजपा यदि भागवत की नसीहत पर तत्काल प्रभाव से अमल करे तो यकीनन वह जल्द ही निराशा के भंवर से उबर सकती है।

भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च होंगी ये 3 नई एसयूवी, जानिए डिटेल्स

महिंद्रा थार फाइव-डोर को भारत में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस ट्रू ब्लू एसयूवी का 5-डोर वर्जन वर्तमान में उपलब्ध तीन-दरवाजे वाले संस्करण के समान सिल्हूट के साथ आएगा। इस साल भारत में आने वाली एक प्रमुख एसयूवी टाटा कर्व है जो देश में सबसे अधिक प्रतीक्षित कारों में से एक है। कर्व एक कूप एसयूवी है और इसके त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। भारतीय कार बाजार में लगातार SUVs की मांग बढ़ रही है। मौजूदा समय में लोग बॉक्सी और हाई-राइडिंग SUV खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसका असर छोटी कारों और सेडान की बिक्री संख्या पर पड़ रहा है। उपभोक्ताओं की इस बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए इंडियन कारमेकर जल्द ही 3 नई एसयूवी पेश करने जा रहे हैं। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं।

Mahindra Thar 5-door

महिंद्रा थार फाइव-डोर को भारत में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस ट्रू ब्लू एसयूवी का 5-डोर वर्जन वर्तमान में उपलब्ध तीन-दरवाजे वाले संस्करण के समान सिल्हूट के साथ आएगा। हालांकि, उम्मीद है कि महिंद्रा कार को थार थ्री-डोर से अलग बनाने के प्रयास में कुछ स्पेसिफिक एलीमेंट जोड़ेगी।

इसे संभावित रूप से महिंद्रा थार अर्माडा नाम दिया जाएगा और इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन होने की उम्मीद है, जो 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़े गए हैं।

Tata Curvv

इस साल भारत में आने वाली एक प्रमुख एसयूवी टाटा कर्व है, जो देश में सबसे अधिक प्रतीक्षित कारों में से एक है। टाटा कर्व एक कूप एसयूवी है और इसके त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च होने की उम्मीद है।

यह इलेक्ट्रिक और ICE दोनों अवतारों में उपलब्ध होगी। कर्व के ICE संस्करण के हुड के नीचे, 1.5-लीटर डीजल इंजन और एक नया TGDi टर्बो-पेट्रोल मोटर होने की उम्मीद है, जबकि एक CNG संस्करण भी हो सकता है।

MG Gloster facelift

MG Motor India पिछले कुछ सालों से Gloster facelift को भारतीय बाजार में टेस्ट कर रही है। एसयूवी के प्रोटोटाइप की सड़क पर की गई टेस्टिंग से संकेत मिलता है कि एमजी जल्द ही देश में ग्लोस्टर के नए वर्जन को लॉन्च करने का लक्ष्य बना रही है।

भारत में फ्लैगशिप एमजी एसयूवी एक नए एक्सटीरियर डिजाइन के साथ-साथ अंदर और बाहर कई अपडेटेड फीचर्स के साथ आएगी। हुड के नीचे, ग्लोस्टर फेसलिफ्ट उसी 2.0-लीटर डीजल इंजन द्वारा संचालित होगी, जो टर्बोचार्ज्ड और ट्विन-टर्बो ट्रिम विकल्पों में उपलब्ध होगी। ट्रांसमिशन विकल्प में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल होगा।

BMW 5 Series LWB भारतीय बाजार में 24 जुलाई को होगी लॉन्च, जानें डिटेल्स

नई दिल्ली। BMW India भारतीय बाजार में 24 जुलाई को पहली बार 5 Series LWB पेश करने जा रही। लग्जरी कारों की बिक्री बढ़ने के साथ, निर्माता बढ़ती मांग को भुनाने के लिए जल्दी-जल्दी वैश्विक मॉडल लाने की सोच रहा है।

BMW 5 Series LWB में क्या खास?

नवीनतम BMW 5 Series को कुछ महीने पहले आठवीं पीढ़ी की 5 सीरीज की शुरुआत के बाद इलेक्ट्रिक i5 LWB के साथ अगस्त 2023 में चीन में पेश किया गया था। यह सीधे मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास LWB को कंपीट करेगी, जिसे इस कैलेंडर वर्ष के अंत में अपडेट किया जाना है। नियमित मॉडल की तुलना में ये 145 मिमी लंबी होगी और इसका व्हीलबेस 3,105 मिमी होगा।

डिजाइन और डायमेंशन

चीन में इसकी लंबाई 5,175 मिमी, चौड़ाई 1,900 मिमी और ऊंचाई 1,520 मिमी है और भारत-स्पेक संस्करण में मामूली बदलाव की उम्मीद है। यह घरेलू बाजार में रिटेल की जाने वाली 3 सीरीज ग्रैंड लिमो के साथ आएगी और दिखने में स्टैंडर्ड 5 सीरीज जैसी ही है, क्योंकि इल्यूमिनेटेड फ्रंट ग्रिल डिजाइन, हेडलैंप और टेल लैंप एक जैसे हैं।

इंजन और परफॉरमेंस

बंपर में ट्रिम लेवल के आधार पर मामूली अपडेट मिलेंगे और होफमिस्टर किंक पर इल्यूमिनेटेड 5 एम्बलम मिल सकता है। परफॉर्मेंस के लिए, नई BMW 5 सीरीज 2.0L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और डीजल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होने की उम्मीद है। दोनों को मानक के रूप में 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जाएगा।

इंटीरियर और फीचर्स

इक्विपमेंट लिस्ट में 5G कनेक्टिविटी और 8K रिजॉल्यूशन के साथ एक बड़ी 31.1-इंच पैनोरमिक डिस्प्ले स्क्रीन, B&W ऑडियो, 3-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, 4-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दो-रंग की क्विल्टेड सीट अपहोल्स्ट्री, टाइटेनियम ब्रॉन्ज एक्सेंट, क्राफ्टेड क्लैरिटी ग्लास ट्रीटमेंट के साथ कंट्रोल और बहुत कुछ शामिल होगा।

नवीनतम BMW 5 Series को कुछ महीने पहले आठवीं पीढ़ी की 5 सीरीज की शुरुआत के बाद इलेक्ट्रिक i5 LWB के साथ अगस्त 2023 में चीन में पेश किया गया था। यह सीधे मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास LWB को कंपीट करेगी। चीन में इसकी लंबाई 5175 मिमी चौड़ाई 1900 मिमी और ऊंचाई 1520 मिमी है और भारत-स्पेक संस्करण में मामूली बदलाव की उम्मीद है।

हुंडई इन्स्टर EV की पहली झलक आई सामने, जानिए कितनी खास होगी ये Micro SUV

Hyundai ने हाल ही में एक नई ऑल-इलेक्ट्रिक माइक्रो-एसयूवी Inster को पेश किया है। कंपनी ने कहा कि Inster नाम को intimate और innovative शब्दों से लिया गया है। । हुंडई ने वादा किया है कि इंस्टर अपनी श्रेणी में प्रतिस्पर्धी होगी। इसमें भारत में लोकप्रिय टाटा टियागो ईवी के समान एक बार चार्ज करने पर 315 किलोमीटर की WLTP की क्लेम्ड ड्राइविंग रेंज शामिल है।

नई दिल्ली। Hyundai ने हाल ही में एक नई ऑल-इलेक्ट्रिक माइक्रो-एसयूवी को पेश किया है। कंपनी ने इसे Hyundai Inster नाम दिया है। इसे महीने के अंत में कोरिया में बुसान इंटरनेशनल मोटर शो 2024 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जाएगा, जो 27 जून से 7 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा।

Hyundai Inster के नाम की कहानी

कंपनी ने कहा कि Inster नाम को intimate और innovative शब्दों से लिया गया है। मौजूदा कैस्पर प्लेटफॉर्म पर निर्मित, हुंडई इंस्टर ने ICE समकक्ष (कैस्पर) से गोल हेडलाइट्स जैसे डिजाइन संकेतों को उधार लिया है।

डिजाइन और इंटीरियर

हालांकि, यह हुंडई की नवीनतम ईवी की याद दिलाने वाली विशिष्ट पिक्सेलेटेड एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स के साथ एक आधुनिक टच जोड़ती है। हुंडई ने वादा किया है कि इंस्टर अपनी श्रेणी में प्रतिस्पर्धी होगी। इसमें भारत में लोकप्रिय टाटा टियागो ईवी के समान एक बार चार्ज करने पर 315 किलोमीटर की WLTP की क्लेम्ड ड्राइविंग रेंज शामिल है। अंदर की एक झलक पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले को दिखाती है, जो टेक-सेंट्रिक केबिन का संकेत देती है।

Hyundai का फ्यूचर प्लान

हुंडई भारतीय बाजार के लिए कई EVs प्लान कर रही है। इन इलेक्ट्रिक वाहनों में पहली पेशकश क्रेटा ईवी होगी, जिसके विवरण का खुलासा होना बाकी है। कंपनी का लक्ष्य 2024 के अंत तक चेन्नई प्लांट में अपने पहले इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना है।

इस पहल का समर्थन करने के लिए, हुंडई मोटर इंडिया ने 2030 तक 485 चार्जिंग स्टेशनों को लक्षित करते हुए अपने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने की योजना बनाई है।

सिंगल चार्ज पर 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देते हैं ये किफायती E-Scooters, देखिए टॉप-5 की लिस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

Ola S1 X भारत में किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 190 किलोमीटर की ARAI-क्लेम्ड रेंज प्रदान करता है। ओला एस1 एक्स भारत में किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 190 किलोमीटर की ARAI-क्लेम्ड रेंज प्रदान करता है। आइए अन्य ई-स्कूटरों के बारे में भी जान लेते हैं।

नई दिल्ली। देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। खासकर, E-Scooters को लेकर लोगों की रुचि बढ़ी है। अगर आप भी डेली कम्यूटिंग के लिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए ऐसे 5 किफायती ई-स्कूटरों की लिस्ट लेकर आए हैं।

Ola S1 X

ओला एस1 एक्स भारत में किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 190 किलोमीटर की ARAI-क्लेम्ड रेंज प्रदान करता है। आप इसे 99,999 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर खरीद सकते हैं।Ola S1 X में 4 kWh की बैटरी और हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया गया है। 90 किमी प्रति घंटे की टॉप-स्पीड के साथ, ई-स्कूटर 5.5 सेकंड में 0-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है।

Pure EV ePluto 7G

Pure EV Pluto 7G एक किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी कीमत 92,999 रुपये (एक्स-शोरूम, भारत) है। इस ई-स्कूटर में 2.4 kWh की बैटरी और हब-माउंटेड BLDC मोटर दिया गया है। यह 111 किमी - 151 किमी के बीच की रेंज और 72 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड प्रदान करती है।

Bajaj Chetak 2901

बजाज ऑटो ने आज भारत में अपना सबसे किफायती चेतक 2901 ई-स्कूटर 95,998 रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) में लॉन्च किया। चेतक का ये स्पेशल एडिशन एक बार चार्ज करने पर 123 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज प्रदान करता है। इसमें रंगीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और जियो-फेंसिंग के अलावा अन्य कई फीचर्स दिए गए हैं।

Ampere Magnus EX

Ampere Magnus EX भारतीय बाजार में 94,900 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 2.2 kWh की बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 100 किमी से ज्यादा की प्रमाणित रेंज देती है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 10 सेकंड के अंदर 0-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। इसकी टॉप स्पीड 53 किमी प्रति घंटा है।

Komaki SE Eco

Komaki SE Eco की कीमत 97,256 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक बार चार्ज करने पर 95-100 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है। 3 kW BLDC मोटर से लैस, हाई-स्पीड ई-स्कूटर में तीन राइड मोड-इको, टर्बो और स्पोर्ट मिलते हैं।

विपक्ष की गारंटियों के बावजूद एनडीए को बहुमत

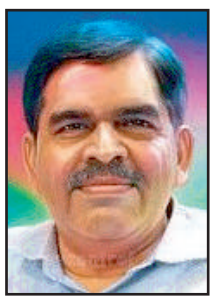

डा. अश्विनी महाजन

आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत देश में विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी, ताकि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। देश में बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करने होंगे। यह सही है, पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन तकनीक के साथ तालमेल बने'

2024 का आम चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं की अपेक्षा से कम सीटें पाने में सफल रही, लेकिन एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश जरूर मिला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुआई वाला एनडीए पिछले दस सालों के अपने काम और प्रदर्शन पर वोट मांग रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन मोदी सरकार के दौरान महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहा था। एक तरफ नरेंद्र मोदी 'जीवन को आसान बनाने' की गारंटी और अपनी नीतियों के साथ लोगों तक पहुंच रहे थे, जिसमें गरीबों के लिए आवास, अगले 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन, गरीबों के साथ-साथ 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत मुफ्त इलाज, किसान सम्मान निधि और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना शामिल था। लेकिन कांग्रेस जो कि इंडी गठबंधन की मुख्य पार्टी थी, वह पिछले चुनावों की तरह ही, हर गरीब परिवार को एक लाख रुपए की राशि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, जाति आधारित सर्वेक्षण करके धन का पुनर्वितरण (जनसंख्या के अनुसार) आदि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में थी। इंडी गठबंधन में शामिल अन्य क्षेत्रीय दल भी मुफ्त योजनाओं का लालच देकर जनता को लुभा रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने मुफ्त योजनाओं के लिए वोट नहीं दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को जीत दिलाई। यह साबित करता है कि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी के दस साल के कार्यकाल के दौरान अपनाई गई नीतियों का समर्थन करके एनडीए को विजयी बनाया है, हालांकि उस भारी बहुमत के साथ नहीं, जिसका दावा सत्तारूढ़ गठबंधन कर रहा था, खासकर तीन बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में।

लाभार्थियों का समर्थन

हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गरीबों के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं, जिनके लाभार्थियों ने स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। लाभार्थियों की बात करें तो 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पक्के मकानों का निर्माण नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। गौरतलब है कि जो गरीब परिवार पहले कच्चे या अर्ध-कच्चे मकानों में रहते थे, उनके लिए पिछले कुछ सालों में करीब 3 करोड़ ग्रामीण और एक करोड़ शहरी मकान बनाए गए। अगर पांच लोगों के परिवार को माना जाए तो करीब 20 करोड़ लोग इस योजना के लाभार्थी रहे हैं। समझा जा सकता है कि इस योजना ने उन गरीब परिवारों की कुशलता और जीवन स्तर में बड़ा बदलाव लाया है। स्वाभाविक रूप से एनडीए को इन लाभार्थियों का समर्थन मिला है। इसके साथ ही गरीबी के कारण एलपीजी कनेक्शन से वंचित 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत न सिर्फ धुएं से मुक्ति मिली है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन लाभार्थियों ने भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन किया है। वैसे तो महिला स्वाभिमान के प्रतीक शौचालयों के निर्माण को सामाजिक क्रांति माना जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस योजना के कारण खुले में शौच से मुक्त हुई महिलाओं का समर्थन भी मौजूदा सरकार चला रही पार्टियों को मिला होगा। लगभग पूरे देश को नल से जल और शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना किसी क्रांति से कम नहीं माना जा सकता। करीब 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन और किसानों को 6 हजार रुपए प्रति वर्ष की राशि जारी रखने की गारंटी भी एक लोकप्रिय कदम माना जा रहा है। समझना होगा कि किसान सम्मान निधि को छोड़कर, जिसका असर करीब 75000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकारी खर्च पर पड़ता है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई भी अन्य योजना नकद वितरण वाली नहीं थी।

कांग्रेस की नकद वितरण योजना उसे वोट नहीं दिला पाई

इससे पहले भी कांग्रेस ने किसानों के 70000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे और 2024 में भी इसी तरह की घोषणा की गई थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद हर गरीब परिवार को सालाना 72000 रुपए देने का वादा किया था और तब भी कांग्रेस को लोकसभा में सिर्फ 52 सीटें ही मिलीं। यानी तब भी लोगों ने कांग्रेस की नकद वितरण योजना को नकार दिया था। इस बार कांग्रेस ने चुनाव के दौरान हर गरीब परिवार को सालाना एक लाख रुपए देने का वादा किया था और इसका खूब प्रचार भी किया था। हालांकि, कांग्रेस के इस वादे के क्रियान्वयन को लेकर लोगों में काफी संदेह था और कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर, सरकार में शामिल होने के लिए जादुई संख्या से काफी कम 100 से कुछ कम ही रहीं। एक तरफ जनता द्वारा नकद वितरण योजना को नकारना और दूसरी तरफ मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं पर दिखाया जा रहा भरोसा, देश के मतदाताओं और लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है।

नई सरकार की क्या होंगी प्राथमिकताएं?

देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। यह सच है कि पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है और देश दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन यह भी सच है कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच असमानता अभी भी बनी हुई है। हालांकि, अत्यधिक गरीबी में काफी कमी आई है, लेकिन मोदी सरकार के पहले नौ वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के बावजूद बहुआयामी गरीबी से पीड़ित लोगों की संख्या वर्ष 2023 तक 12 करोड़ बनी हुई थी। यह सही है कि राजकोषीय सूझबूझ के कारण सरकार का पूंजी निवेश बढ़ रहा है, देश में बड़ी मात्रा में बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है, जिससे देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने में सफलता मिल रही है। दूसरी ओर, तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन लेन-देन दुनिया में कहीं और की तुलना में भारत में कहीं अधिक हो रहा है, सरकार अधिक से अधिक पेटेंट देने में भी सफल रही है, और अंततः वर्ष 2014 में केवल 4227 पेटेंट की तुलना में वर्ष 2024 में 1.03 लाख पेटेंट दिए गए, जो देश में नवाचार में विकास को दर्शाता है।

हालांकि, उत्पादों के निर्माण में हमारी निर्भरता अभी भी विदेशों पर बनी हुई है। आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत देश में विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी, ताकि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। देश में बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करने होंगे। यह सही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारण पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखना भी जरूरी होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मशीनों और एआई का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में कम हो, जहां श्रम का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही, ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और कृषि तथा उससे जुड़ी गतिविधियों को विकसित करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करने होंगे। सरकार को खाली पड़े पदों पर भर्ती भी करनी चाहिए।

संपादक की कलम से

अहमियत के दरवाजे

भारत में भविष्य और भविष्य में भारत देख रही भाजपा का सत्ता में लौटना जैसे ही 'एनडीए' हो गया, मंत्रिमंडल के कुनबे में कुछ चेहरे छंट गए। पांचवीं बार के सांसद और भाजपा की अग्रिम पंक्ति के युवा नेता अनुराग ठाकुर का पहली सूची में मंत्रिमंडल का सदस्य न बनना हिमाचल को हैरान करता है, हालांकि प्रदेश के ही जगत प्रकाश नड्डा अपनी अहमियत के दरवाजे पुनः मोदी मंत्रिमंडल में खोल चुके हैं। सवाल यहां उस अंक गणित का है जिसके तहत जनता ने चारों सीटें यानी सौ फीसदी जीत भाजपा के नाम इसलिए कर दी ताकि प्रदेश का रुतबा केंद्रीय सरकार में बढ़े। क्या यह अनुराग को सबक या नड्डा का फलक है या भाजपा के संगठन में ठाकुर की किश्ती तैर रही है। जो भी हो, बतौर सांसद व मंत्री अनुराग ठाकुर की उपलब्धियां निजी व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए श्रेष्ठ ही रही हैं। एक वही ऐसे सांसद हिमाचल के इतिहास में सामने आए जिन्होंने केंद्रीय प्रभाव से अपने विकास के मजमून सुदृढ़ कर दिए। खास तौर पर ऊना रेल परियोजना के मार्फत दौड़ रहीं दर्जन भर ट्रेनें, एम्स, हमीरपुर मेडिकल कालेज, ऊना में पीजीआई सेटेलाइट सेंटर, हमीरपुर में खेल परिसर, स्वां तटीकरण व बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना में उनकी खास भूमिका रही है। यह दीगर है कि वह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ही मंत्री साबित हुए, वरना बतौर खेल मंत्री पूरा हिमाचली अपनी आबोहवा के बूते खेल राज्य बनने के तौर तरीके व वांछित ढांचा सुदृढ़ कर लेता।

यहां कई ऐसे सियासी मंजर भी सामने आते हैं जहां हिमाचल की आंतरिक स्थिति केंद्रीय पदों के आबंटन में उलझती है। यह इसलिए भी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लंबा कार्यकाल व गुजरात के कोटे से राज्यसभा पहुंच कर जगत प्रकाश नड्डा कुछ उनके सांसद हो गए हैं, तो माना यह जा रहा है कि वह भाजपा के राष्ट्रीय महत्त्व के धूमकेतु हैं और रहेंगे। बतौर स्वास्थ्य मंत्री बिलासपुर एम्स निर्माण में उनके नाम की चर्चा हमेशा होगी, लेकिन बतौर मंत्री समूचे प्रदेश के लिए उनके योगदान में भी भारी कमी रही है। हिमाचल में भाजपा सियासत को पढ़ने के लिए केंद्र की नजदीकियां तथा ओहदे खास महत्त्व रखते हैं। जब केंद्र में अनुराग के मंत्री पदों का आरोहण हो रहा था, तो जगत प्रकाश नड्डा के आभामंडल में पूरा कमल खिल रहा था। इन दो ध्रुवों के बीच सियासी प्रश्रय की सत्ता जिस शख्स के नाम हुई, वह जयराम ठाकुर इस दौरान हिमाचल के कर्ताधर्ता बने और मौजूदा चुनाव आते-आते खूब फूले फले। अंततः नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके पद और विपक्ष के मोर्चे पर पार्टी ने राज्यसभा में एक तथा लोकसभा में चार सांसद बढ़ाए हैं।

इतना ही नहीं, विधानसभा में दो विधायक भी बढ़ रहे हैं, जबकि उपचुनावों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की जीत का तिलक अनुराग ठाकुर के लिए अब सीधा गणित नहीं है। पार्टी अपने संसदीय क्षेत्र में मोदी के नाम पर स्पष्टता से एक सीट जीत रही है, तो वही मतदाता उपचुनाव में दूसरी सलेट पर किस हिसाब से विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में जज्बात उंडेल रहा है। यह कैसा 'एकमत' जो केंद्र में मोदी को प्रधानमंत्री तो हिमाचल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के नाम हो रहा है। बहरहाल अभी समझौते का मंत्रिमंडल, एनडीए का मंत्रिमंडल है, लिहाजा घटक दलों की हिस्सेदारी फल फूल रही है। इस मुकाम पर जो नजर आ रहा है वह स्थायी नहीं, कल ऊंट फिर करवट बदलेंगे तो बात समझ आएगी। उम्मीद यह है कि इस बार नड्डा के नाम पर हिमाचल को संतुष्ट करने के लिए पूर्व राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष को भरमौर से सिरमौर और चन्नौर से किन्नौर तक अपने मंत्रालय और मोदी मंत्रिमंडल का प्रश्रय देते हुए पुरस्कार देना होगा।

राय

गठबंधन के राजधर्म

प्रधानमंत्री मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उसी के साथ नई केंद्र सरकार का राजधर्म आरंभ हो गया। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की विविधता और ताकत का समारोह मनाने का क्षण है। यह चुनाव आयोग, अन्य संस्थानों, कर्मचारियों और प्रक्रिया का आभार जताने का भी पल है। देश के मतदाताओं ने जनादेश दिया है। गठबंधन की यह सरकार भी लोगों की इच्छा की प्रतीक है, क्योंकि गठबंधन में ही बहुमत और राजधर्म निहित हैं। चूंकि यह गठबंधन की सरकार है, किसी एक दल के पक्ष में बहुमत का जनादेश नहीं है, तो उसके मायने ये नहीं हैं कि गठबंधन की निरंतरता और स्थिरता का ही रोना रोया जाए अथवा बहानों के लिए गठबंधन की आड़ में छिपा जाए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही यह एनडीए-3 सरकार है और 2014 की निरंतरता में ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिला है और सरकार की स्थिरता गठबंधन के घटक दलों के सहारे ही है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब 1991 में नरसिम्हा राव सरकार बनी थी, तब कांग्रेस के 232 सांसद ही थे। सरकार पूरे पांच साल चली, यह दीगर है कि कुछ कलंक और दाग लग गए थे, जो लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। सदन में बहुमत साबित करने के लिए सांसदों को खरीदा गया था, कुछ को मंत्री पद का लालच दिया गया था। कमोबेश अब भाजपा के पास 240 सांसद हैं और कुछ निश्चित समर्थक भी हैं। बहुमत के लिए खरीद-फरोख्त की नौबत, शायद, न आए। बहरहाल मौजूदा संदर्भ में हमें तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) और जद-यू की ही चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी समविचारक भारत सरकार की जरूरत है, जो उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कर सके। दोनों ही दलों के राज्य गरीब और विपन्न हैं। दोनों ही राज्य कर्जदार हैं। अन्य सरकार उनकी जरूरतों को संबोधित नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का राजधर्म यह है कि जब भी कोई बड़ा और गंभीर फैसला लेना हो, तो विमर्श की मेज पर सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद हों और फैसला सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री ऐसी भावना व्यक्त कर चुके हैं। गठबंधन सरकारों के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह भी थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल बखूबी निभाए। डॉ. मनमोहन सिंह तो 10 साल तक गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री रहे। दूरसंचार, पेंशन, सरकारी घाटे पर लगाम कसने की व्यवस्था, बिजली और बीमा क्षेत्र के कई बड़े सुधारवादी फैसले वाजपेयी सरकार के दौरान लिए गए। मनमोहन सरकार के दौरान अमरीका के साथ असैन्य परमाणु करार जैसे संवेदनशील फैसले के अलावा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, अनिवार्य-मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, सूचना के अधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून आदि पारित कराए गए। इनके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों को बाजार के हवाले करने सरीखे बड़े फैसले भी लिए गए। चूंकि अब भाजपा अल्पमत में है, लिहाजा एनडीए की गठबंधन सरकार, गठबंधन धर्म और मोदी सरकार के राजधर्म की अग्निपरीक्षा का यह दौर है। हालांकि हमें कोई बड़ा संकट या राजनीतिक दरारों के हालात नहीं लगते, क्योंकि आर्थिक विकास और आर्थिक सुधारों के पक्षधर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी हैं। फिर भी असली चुनौती तब सामने आएगी, जब प्रधानमंत्री टीडीपी और जद-यू दोनों को ही निर्णय की मेज पर बुलाएंगे और सर्वमत नहीं बन पाएगा। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को 'ऑर्गेनिक' और 'सफलतम' गठबंधन करार दिया है। वह जनादेश के मर्म को जानते हैं और अलग-अलग राज्य और दल की भिन्नता महसूस करते हैं, लिहाजा कुछ समझौतापरस्त होना भी अपेक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे केंद्र की कल्पना कर रहे हैं, जो राज्यों को अपने साथ लेकर आगे बढ़े और उनकी बात गौर से सुने। उन्होंने प्रतिस्पद्र्धी और सहकारी संघवाद के मॉडल की भी बात की है।

पिता ईश्वर तुल्य, उनकी सेवा ईश्वर भक्ति

पिता के मरने पर बेटी हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका पिता ही नहीं उसकी वो हिम्मत भी मर जाती है। बेटी के लिए पिता दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड होता है। पिता अपने बेटे के साथ मैत्रीपूर्ण और करीबी रिश्ता हासिल करना चाहता है। पिता को सम्मान देना जरूरी है'

पितृ दिवस बच्चों के लिए अपने पिता और पितातुल्य लोगों के प्रति सराहना दिखाने का दिन है। वयस्कों के लिए यह दिखाने का दिन है कि वे अपने जीवन में पिता और उनकी कड़ी मेहनत को कितना आदर देते हैं। पिता एक ऐसा शब्द है जिसके बिना किसी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसकी तुलना किसी और रिश्ते से नहीं की जा सकती है। बच्चे के लिए उसके पिता ही उसके महानायक होते हैं। बच्चा अपने पिता के साथ चलना और पहला कदम उठाना सीखता है। बचपन में उंगली पकड़ कर चलना और बाहों में रह कर बच्चे को बहुत सुकून मिलता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है 'पिता से जी भर के प्यार ले लो, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक मकबरा है, ईश्वर ने हमें विभिन्न रूपों में प्रेम भेजा है, और उनमें से एक हमारे पिता हैं।' पितृ दिवस एक उत्सव है जो पिता का सम्मान करता है और पितृत्व, पितृ बंधन और समाज में पिता के प्रभाव का जश्न मनाता है। यह दादा, बड़े भाई और ऐसे किसी भी पुरुष अभिभावक सहित अन्य पिता के सम्मान में भी मनाया जाता है। इसी संदर्भ में पूरे विश्व में हर साल जून के तीसरे रविवार को पितृ दिवस मनाया जाता है। 1966 में राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने प्रथम राष्ट्रपतीय घोषणा जारी कर जून महीने के तीसरे रविवार को पिताओं के सम्मान में पितृ दिवस के रूप में तय किया। 1972 में वह दिन आया जब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए और यह एक स्थायी राष्ट्रीय छुट्टी बना।

भारत में भी धीरे-धीरे इसका प्रचार-प्रसार बढ़ता जा रहा है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती भूमंडलीकरण की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है और पिता के प्रति प्रेम के इजहार के परिप्रेक्ष्य में भी। चाणक्य ने कहा है कि संस्कार के हिसाब से हर इनसान के पांच तरह के पिता होते हैं : विद्या देने वाला, भय से रक्षा करने वाला, जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला और अन्नदाता। भारतीय परंपरा में पिता का महत्व अतुलनीय है। संस्कृति, विचार, परवरिश, शिक्षा और संस्कार हमें अपने पिता से ही मिलते हैं। एक पिता को विभिन्न तरीकों से वर्णित किया जा सकता है। वह प्रदाता, रक्षक, उदारकर्ता, निर्माता और वह सब कुछ है। किसी ने ठीक ही कहा है कि 'अब तक का सबसे बड़ा उपहार परमेश्वर की ओर से आया था, मैं उसे पापा कहता हूं।' हमारे ग्रंथों में माता-पिता और गुरु तीनों को ही देवता माना गया है। उनकी सेवा और भक्ति में कसर रह जाए तो फिर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। एक अच्छा पिता होने का मतलब अपने बच्चों की शारीरिक जरूरतें

पूरी करना ही नहीं है। इसमें उनके भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए उपस्थित रहना, संलग्न होना और प्रतिबद्ध होना शामिल है। एक अच्छे पिता की कमी बच्चों के आत्म-सम्मान, रिश्तों और समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जीवन का आधार ही पिता है। पिता से ही घर होता है। पिता ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बिन पिता के जीवन नर्क सा लगता है।

जिन लोगों के पापा जीवित हैं, वे लोग इस दुनिया के बहुत खुशनसीब लोग हैं। जिनके पापा नहीं हैं, वे लोग ही जानते हैं कि पिता के जाने के बाद उन लोगों ने किन-किन मुसीबतों का सामना किया है। 'यूं देखिए तो आंधी में बस एक सजर गया, न जाने कितने परिंदों का घर गया।' हर बच्चा अपने पिता से ही सारे गुण सीखता है जो उसे जीवन भर विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार ढलने के काम आते हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं जो पिता जी को खास बनाती हैं। वे कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोते हैं और धीरज से काम लेते हैं। वे सारे परिवार से प्रेम करते हैं, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते हैं। वे सारी जरूरतें और फरमाइशें भी पूरी करते हैं। वे गलतियों पर डांटते तथा माफ भी कर देते हैं और आगे गलती न करने की सीख भी देते हैं। उनका दिल बड़ा होता है, कई बार उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, फिर भी अपनी जरूरतें भूल कर परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं। संयम पिताजी की खूबसूरती होती है। वे हमेशा अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, वो हमेशा संयमित व्यवहार करते तथा कुशलता से हर कार्य को पूर्ण करते हैं। पिता जी हमेशा हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं और खुद भी अनुशासित रहते हैं। गंभीरता उनका गहना है। पिताजी घर के सभी कार्यों और परिवार के सभी लोगों और उनके स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होते हैं, परंतु खुद की कोई भी तकलीफ नहीं बताते। ये सारी विशेषताएं ही पिता की महानता को और अधिक बढ़ाती हैं। इसलिए उनकी तुलना दुनिया में किसी से भी नहीं की जा सकती। पिता प्रत्येक बच्चे के लिए धरती पर ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं। वे अपनी संतान को सुख देने के लिए अपने सुखों को भुला देते हैं। बिना पिता के मां का सिंदूर व अस्तित्व नहीं होता। पिता का स्थान मां से नीचे नहीं होता। मां को याद करके चोट लगती है, तो पिता की जरूरत पडने पर याद आती है। परंतु माता-पिता एक-दूसरे के पूरक हैं, जरूरत हैं।

एक-दूसरे के बिना वे अधूरे हैं। पिता और पुत्री के बीच इतना प्यार इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों के बीच में एक रिश्ता है जो उन्हें पिता और पुत्री के बंधन में बांधता है। दूसरा, पिता की अपनी पुत्री के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी होती है। बेटी की जिम्मेदारी को निभाते समय पिता कहते हैं : 'रो रहे थे सब तो मैं भी फूट-फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी।' जब तक पिता जिंदा रहता है, बेटी मायके में हक से आती है। पिता के मरने पर बेटी हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका पिता ही नहीं उसकी वो हिम्मत भी मर जाती है। बेटी के लिए पिता दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड होता है। पिता अपने बेटे के साथ मैत्रीपूर्ण और करीबी रिश्ता हासिल करना चाहता है। खिलौने से लेकर बाइक, कार, लैपटॉप और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने तक, सारी मांगें पिता ही पूरी करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब भाग-दौड़ भरी इस जिंदगी में बच्चों के पास अपने माता-पिता के लिए समय नहीं होता। यह स्थिति भारतीय समाज को भी चिंतित करती है।

सत्यपाल वशिष्ठ

पीए सिद्धार्थ

धनानंद अमर है

धनानंद कभी नहीं मर सकता। धनानंद अमर है। हो सकता है कि आप मेरे इस कथन पर कहें कि मगध देश के नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद सैंकड़ों बरस पहले चंद्र गुप्त के साथ हुए युद्ध में मारा गया था या उसकी पुत्री से विवाह करने के उपरांत चंद्र गुप्त ने उसे राजधानी से बाहर जाने की अनुमति दे दी थी। लेकिन ध्यान रखें कि धनानंद व्यक्ति नहीं, ऐसा चरित्र है जो अवसर और अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही फूट पड़ता है। जिस तरह उपजाऊ ज़मीन में बीज डालते ही अंकुर फूट पड़ते हैं, उसी तरह सत्ता का खाद-पानी मिलते ही नए-नवेले शासक के भीतर से धनानंद की कोंपलें फूट पड़ती हैं और देखते-देखते ही आसमान छूने लगती हैं। यक़ीन न हो तो अपने आस-पड़ोस में नजऱ दौड़ाएं। कुछ दिन पहले अपनी धनानंदी के चलते आगरा के डीएम को उनके एक बीडीओ ने जूते से नाप दिया था। भारत के विभिन्न राज्यों में हो रहा बुलडोजऱ न्याय भी धनानंदी का प्रतीक है। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए न्यायालय के आदेशों के बग़ैर उत्तराखंड के हलद्वानी और दिल्ली में गिराए मदरसे और मस्ज़िद धनानंदिया चरित्र के जीते-जागते सुबूत हैं। भारतीय इतिहास में झांक कर देखें तो धनानंदिया चरित्र नंद वंश से काफी पहले सामने आता है। हिरण्यकश्यप और कंस अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु और कृष्ण से उलझ गए थे। पर इधर तो मामला ही कुछ और है। मौजूदा धनानंद भगवान विष्णु और कृष्ण के साक्षात अवतार हैं। दरअसल किसी भी शासन व्यवस्था में नवजात की तरह पैदा होने के बाद धनानंद उसे अपनी बपौती समझते हुए उस पर क़ाबिज़ हो सकता है या क़ाबिज़ होने के लिए आसमान को खींच कर ज़मीन पर लाने की कोशिश कर सकता है। भले वह लोकतंत्र ही क्यों न हो। बस कुरसी मिलनी चाहिए। फिर चाहे थूक के चाटना पड़े या चाट के थूकना।

देश में पिछले दो दशकों से लोकसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को साधने के लिए जिस तरह मुरदों को जिलाया जा रहा है, उससे तो लगता है कि सरकार को भारत रत्न को दो श्रेणियों में बांट देना चाहिए। आम भारत रत्न और चुनावी भारत रत्न ताकि लोगों में संदेह की स्थिति उत्पन्न न हो। रोटी, कपड़ा, मकान और काम से जूझते लोग भले अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर जीते रहें, लेकिन मृतकों के सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जहां तक भारत रत्न प्राप्त करने वालों के वारिसों के आत्म सम्मान का प्रश्न है, तो वह न कभी पुलिस की लाठियां खाकर कम होता है, न कभी सरकार द्वारा उनके बाप से बंगला छीनने पर और न कभी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले शख्स के जीवन काल में उस राजनीतिक दल द्वारा उसे अपमानित करने पर, जिसकी सरकार अब उन्हें सम्मानित कर रही है। कभी अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि कहने वाले एक भारत रत्नी के वारिस जयंत चौधरी ने गाल बजाते हुए कहा था कि वह कोई चवन्नी नहीं कि केन्द्र सरकार की जांच एंजेसियों के डर से भाजपा में शामिल हो जाए। लेकिन भारत रत्न के लिए अपने दादा के नाम की घोषणा के बाद जयंत जिस तरह से पिघला है, उससे लगता है कि उसकी क़ीमत इकन्नी से भी कम हो गई है। हिंदी फिल्म 'ओम शांति ओम' में दीपिका पादुकोण द्वारा बोले गए डायलॉग 'एक चुटकी सिन्दूर की क़ीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू!' की तरह अब जयंत चौधरी का नया डायलॉग हो सकता है, 'एक चवन्नी क़ीमत तुम क्या जानो, नमो बाबू!' लेकिन भाजपा में शामिल होने की सहमति के बाद उसके चवन्नी से इकन्नी होने पर मैं भारत रत्न के मूल्य का निर्धारण नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपके पास कोई फार्मूला है तो मेरे साथ साझा कर सकते हैं। अन्यथा देश के पास धनानंद द्वारा दिया गया 'ए प्लस बी प्लस टूएबी' का वह फार्मूला तो है ही, जिसकी गणना के आधार पर कुछ सालों में भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है।

पीए सिद्धार्थ

इक्सिगो के आईपीओ पर टूटे निवेशक, जानिए ग्रे मार्केट में क्या चल रहा भाव

परिवहन विशेष न्यूज

Ixigo के शेयरों का एक लॉट साइज 161 शेयरों का है। इसका मतलब कि आपको कम से कम 161 शेयर यानी 1 एक लॉट खरीदना होगा। अगर आप IPO के अपर प्राइस बैंड यानी 93 रुपये के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको 14973 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 2093 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं।

नई दिल्ली। ट्रैवल एग्रीगेटर इक्सिगो (Ixigo) की पैरेंट कंपनी ले ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी के इनिशियल पब्लिक ऑफर को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी ने आईपीओ से 740.10 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बनाया है। Ixigo IPO का प्राइस बैंड 88 से 93 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। यह 10 जून से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और इसे 12 जून तक सब्सक्राइब किया जा सकता है।

कितने शेयरों का लॉट साइज

Ixigo के शेयरों का एक लॉट साइज 161 शेयरों का है। इसका मतलब कि आपको कम से कम 161 शेयर यानी 1 एक लॉट खरीदना होगा। अगर आप IPO के अपर प्राइस बैंड यानी 93 रुपये के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको 14,973 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 2093 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके लिए कुल 194,649 रुपये का निवेश करना होगा।

ग्रे मार्केट में क्या है शेयरों का भाव?

आज ixigo IPO GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) 24 रुपये है। सोमवार को भी यह इसी स्तर पर था। इसका मतलब कि ixigo का आईपीओ 24 रुपये के प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है। शेयर मार्केट के जानकारों का कहना है कि दलाल स्ट्रीट में काफी उतार-चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन ixigo IPO GMP स्थिर रहा। यह आईपीओ निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अगर ixigo IPO की बुकिंग की बात करें, तो इसे मंगलवार दोपहर तक 5 गुना से अधिक सब्सक्राइब कर लिया गया था।

क्या करती है ले ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी?

ले ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड की नींव 2006 में पड़ी। यह एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी (OTA) है। यह ट्रैवलर्स को 'ixigo' ऐप के जरिए बस, ट्रेन और फ्लाइट का टिकट बुक करने की सुविधा देती है। आप इससे होटल भी बुक कर सकते हैं।

ixigo ऐप में PNR स्टेटस और कंफर्मेशन प्रिडिक्शन, ट्रेन सीट अवेलेबिलिटी अलर्ट, ट्रेन रनिंग स्टेटस, फ्लाइट स्टेटस, ऑटोमेटेड वेब चेकिंग जैसे फीचर भी मिलते हैं। अगर कर्मचारियों की बात करें, तो पिछले साल के आखिर तक कंपनी में करीब 500 लोग काम कर रहे थे।

क्या है 8-4-3 फॉर्मूला, जो आपको सिर्फ 15 साल में बना देगा करोड़पति?

परिवहन विशेष न्यूज

अगर आपको 8-4-3 फॉर्मूले से करोड़पति बनना है तो ऐसी स्कीम तलाशनी पड़ेगी जिसमें आपको कम से कम 12 फीसदी का रिटर्न मिले। इसमें खास मुश्किल नहीं होगी। देश के टॉप 10 लार्जकैप फंड्स ने पिछले 10 साल में औसतन 16-18% तक का सालाना रिटर्न दिया है। ऐसे में आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए निवेश कर सकते हैं जो आपको भरोसेमंद लगे।

नई दिल्ली। अमीर बनना हर किसी का ख्वाब होता है। लेकिन, कई लोगों को लगता है कि सिर्फ बिजनेस करके ही अमीर बना जा सकता है। लेकिन, हम आपको ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं, जिससे कोई भी नौकरीपेशा शख्स आराम से करोड़पति बन सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा सिरदर्दी पालने की भी जरूरत नहीं होगी।

12% रिटर्न वाली स्कीम तलाशें

अगर आपको 8-4-3 फॉर्मूले से करोड़पति बनना है, तो ऐसी स्कीम तलाशनी पड़ेगी, जिसमें आपको कम से कम 12 फीसदी का रिटर्न मिले। इसमें खास मुश्किल नहीं होगी। देश के टॉप 10 लार्जकैप फंड्स ने पिछले 10 साल में औसतन 16-18 फीसदी तक का सालाना रिटर्न दिया है। ऐसे में आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए निवेश कर सकते हैं, जो आपको भरोसेमंद लगे।

8-4-3 नियम को फॉलो करें

8-4-3 का नियम (Rule of 8-4-3) बहुत सिंपल है। इसके मुताबिक, आप किसी ऐसी स्कीम में निवेश करें, जिसमें 12 फीसदी की दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज (yearly compounding interest) मिले। इस स्कीम में हर महीने 21,250 रुपये जमा करने पर 8 साल में 33.37 लाख रुपये हो जाएंगे। यह होगा करोड़पति बनने की दिशा में पहला पड़ाव।

आसान होगी आगे की राह

आपको पहले 33.37 लाख रुपये में आठ साल लगेंगे, लेकिन आगे के पैसे आप काफी कम समय में जुटा लेंगे। अगले 33 साल जमा करने में आपको सिर्फ 4 साल लगेंगे यानी पहले वाले 33 लाख के मुकाबले आधा समय। वहीं, आखिरी का 33.33 लाख रुपये तो सिर्फ तीन साल में जुटाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ 15 साल (8+4+3) में करोड़पति बन जाएंगे।

अगले 6 साल में 2.22 करोड़

अगर आप 15 साल बाद भी हर महीने 21,250 रुपये जमा करना जारी रखते हैं, तो 21 साल बाद आपके पास कुल 2.22 करोड़ रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब कि 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ 22 लाख रुपये तक पहुंचने में सिर्फ 6 साल लगेंगे। 22वें साल में तो सिर्फ 12 महीने में ही आपके खाते में 33 लाख रुपये आ जाएंगे।

ये है 'आठवें अजूबे' का कमाल

यह सारा कमाल है, सालाना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, जिसे कभी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का आठवां अजूबा बताया था। निवेश पर ब्याज दो तरीके से मिलता है, साधारण ब्याज (Simple Interest) या फिर चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)। सिंपल रिटर्न में आपके प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूल धन पर ही ब्याज मिलता है। जैसे कि आप जितने पैसे जमा करेंगे, आपको उसी पर ब्याज मिलेगा।

लेकिन, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मूलधन पर जो ब्याज मिलता है, वह भी मूलधन में जुड़ जाता है और फिर उस पर भी ब्याज मिलता है। जैसे कि आपने 1 लाख रुपये जमा किया और उस पर आपको 5 हजार ब्याज मिला, तो अगले साइकल में आपको 1 लाख 5 रुपये पर ब्याज मिलेगा। आसान शब्दों में, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के साथ आपका मूलधन भी बढ़ता है। वहीं, साधारण ब्याज में आपका मूलधन जस का तस रहता है।

शेयर मार्केट में हुआ उलटफेर तो कुछ देर के लिए बंद होगा कारोबार, नहीं होगी शेयर की खरीद-बिक्री

जहां एक तरफ आम जनता लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है तो वहीं ट्रेडर्स बाजार की तेजी पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल जब भी शेयर बाजार में अचानक से शानदार तेजी आती है तो निवेशकों को बचाने के स्टॉक एक्सचेंज सर्किट ब्रेकर लगाते हैं।

नई दिल्ली। जहां एक तरफ आम जनता लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है तो वहीं ट्रेडर्स बाजार की तेजी पर नजर बनाए हुए हैं। सोमवार के सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी देखने को मिली थी। ऐसे में जहां निवेशकों को मुनाफा हुआ था तो वहीं उन्हें नुकसान का डर भी है।

शेयर बाजार का इलेक्शन के साथ कनेक्शन है यह तो सोमवार के सत्र में पूरी तरह से साफ है। लेकिन डर है कि अगर शेयर बाजार में उलट-फेर हुआ तो निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो शेयर बाजार में उलटफेर की आशंका कम ही है, लेकिन फिर भी स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए तैयार है।

दरअसल, निवेशकों में बाजार में तेज उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज सर्किट ब्रेकर (Circut Breaker) लगाता है। आज भी बाजार में यह सर्किट ब्रेकर लग सकते हैं।

क्या होता है सर्किट ब्रेकर

2 जुलाई 2001 में स्टॉक एक्सचेंज ने इंडेक्स-बेस्ड मार्केट-वाइड सर्किट ब्रेकर लागू किया था। यह ब्रेकर शेयर मार्केट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यब ब्रेकर 3 स्टेज में लगते हैं। स्टॉक मार्केट में 10 फीसदी, 15 फीसदी और 20 फीसदी के उतार-चढ़ाव पर यब ब्रेकर लगते हैं।

आपको बता दें कि सर्किट ब्रेकर में सभी इक्विटी और इक्विटी डेरीवेटिव मार्केट एक समयसीमा तक बंद रहते हैं। इसका मतलब है कि तय सीमा तक निवेशक शेयर की खरीद-बिक्री नहीं कर सकते हैं।

इनसाइड

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में मिलेंगी लाखों जॉब्स, कार्यभार संभालते ही मंत्री जितिन प्रसाद ने कही ये बात

मंगलवार को वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र में आने वाले समय में युवा प्रतिभाशाली भारतीयों के लिए लाखों नए रोजगार का विकल्प पेश किए जाएंगे। जितिन प्रसाद पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस परिवर्तन का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।

नई दिल्ली। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने युवा, प्रतिभाशाली भारतीयों के लिए लाखों नई नौकरियां पेश करने में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के आशाजनक भविष्य पर प्रकाश डाला। प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस महत्वपूर्ण भूमिका को सौंपे जाने पर अपना सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने पिछले दशक में उद्योग के विकास और परिवर्तन का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व में लागू की गई दूरदर्शी सरकारी पहलों और योजनाओं को दिया। मंत्री ने डिजिटल युग में कुशल कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के युग में खासकर कुशल युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक की तरह काम करता है। उन्होंने भारत को वैश्विक आईटी और प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया, जो पिछले दस वर्षों में सरकार के लगातार प्रयासों में स्पष्ट है।

पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त आई या नहीं? यहां दूर करें कन्फ्यूजन

नरेंद्र मोदी ने कल से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लिया। वह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सोमवार को कार्यभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने के लिए हस्ताक्षर किये थे। अब ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या सच में 17वीं किस्त जारी हो गई है?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने कल से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लिया। वह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सोमवार को कार्यभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त (PM Kisan Yojana 17th Installment) जारी करने के लिए हस्ताक्षर किये थे। उन्होंने बताया था कि नई सरकार किसान के विकास के लिए काम करेगी।

आपको बता दें कि 17 वीं किस्त का लाभ देश के 9.3 करोड़ों किसानों को मिलेगा। सरकार 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपये बांटेंगी।

अब कई किसानों को लग रहा है कि 17वीं किस्त जारी हो गई है। वहीं कई किसान किस्त की राशि न मिलने की वजह से परेशान है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार ने 17वीं किस्त जारी नहीं की है। पीएम मोदी ने केवल पीएम किसान योजना के ऑफिशियल फाइल पर सिग्नेचर किया है।

पीएम किसान योजना के बारे में

केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी।

इस योजना में किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए सरकार सालाना 6,000 रुपये की राशि देता है। यह राशि किस्तों में मिलती है। हर किस्त में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि आती है। 28 फरवरी 2024 को सरकार ने पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी की थी।

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। अगर किसान ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसान योजना के पात्रता मापदंड में नहीं आता है तब वह योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

कैसे करें ई-केवाईसी

किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ऑनलाइन ई-केवाईसी के लिए किसान को पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं ऑफलाइन ई-केवाईसी के लिए किसान को नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होगा।

एक्शन में आई मोदी सरकार, राज्यों को जारी हुई 1.4 लाख करोड़ रुपये की किस्त, इस राज्य में ट्रांसफर हुई सबसे ज्यादा राशि

सोमवार से देश में मोदी सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया। अपने कार्यभार संभालने के साथ ही मोदी 3.0 एक्शन में दिखी। कल प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17 वीं किस्त के अधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर किये हैं। वहीं आज केंद्र सरकार ने राज्यों को Tax Devolution की 139750 करोड़ रुपये की किस्त जारी कर दी है।

नई दिल्ली। सोमवार से देश में मोदी सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया। अपने कार्यभार संभालने के साथ ही मोदी 3.0 एक्शन में दिखी। कल प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17 वीं किस्त के अधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर किये हैं। वहीं आज केंद्र सरकार ने राज्यों को Tax Devolution की 1,39,750 करोड़ रुपये की किस्त जारी कर दी है।

इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसलाविभिन्न राज्यों की विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए लिया गया ताकि कोई भी परियोजना पूंजी की आवश्यकता के कारण विलंबित न हो।

इस राज्य को मिला ज्यादा पैसा

इस साल मार्च में पेश हुए अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को Tax Devolution के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान था। आज जारी हुई रिलीज के अनुसार अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल राशि 2,79,500 करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलग राशि वितरित की है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिलीज के अनुसार सबसे ज्यादा राशि उत्तर प्रदेश को मिली है। केंद्र सरकार ने यूपी को 25069.88 करोड़ रुपये दिए। वहीं दूसरे नंबर पर बिहार आता है। केंद्र सरकार ने बिहार को 14056.12 करोड़ रुपये दिये हैं। मध्य प्रदेश को 10970.44 करोड़ रुपये दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने जारी किए गए धन का राज्य-वार विस्तृत विवरण प्रदान किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक राज्य को अपनी विशिष्ट विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित हिस्सा मिले।

जैसा कि भारत वैश्विक आर्थिक गतिशीलता की जटिलताओं से जूझ रहा है, देश की वृद्धि को बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्र सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण है।

गठबंधन सरकार के बावजूद बनी रहेगी विकास की तेज रफ्तार, मॉर्गन स्टेनली ने जताया भरोसा

परिवहन विशेष न्यूज

मॉर्गन स्टेनली इंडिया के एमडी रिद्धम देसाई ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में सरकार बुनियादी सुधारों को लागू करेगी जिससे भारत के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि अगर 2014 से 2019 को छोड़ दें तो भारत में 1989 से ही गठबंधन सरकार का दौर चल रहा है। रिद्धम ने भरोसा जताया कि मौजूदा सरकार पांच का कार्यकाल पूरा करने में सफल होगी।

नई दिल्ली। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली भारत में गठबंधन सरकार बनने के बावजूद अर्थव्यवस्था को लेकर काफी आशावादी है। उसका मानना है कि गठबंधन सरकार भी नीतिगत सुधारों पर जोर बना रहेगा और देश की तरक्की की रफ्तार भी बरकरार रहेगी।

मॉर्गन स्टेनली इंडिया के एमडी रिद्धम देसाई ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में सरकार बुनियादी सुधारों को लागू करेगी, जिसका भारत के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। उन्होंने गठबंधन सरकार के सवाल पर कहा कि अगर 2014 से 2019 को छोड़ दें, तो भारत में 1989 से ही गठबंधन सरकार का दौर चल रहा है। रिद्धम ने भरोसा जताया कि मौजूदा सरकार पांच का कार्यकाल पूरा करने में सफल होगी।

मौजूदा आर्थिक नीतियां जारी रहेंगी

रिद्धम ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि सरकार की आर्थिक नीतियों में किसी तरह का बदलाव होने वाला है। सरकार का जोर मैक्रो लेवल पर स्थिरता लाने पर रहेगा। वह सप्लाई चेन बनाने पर भी काम करेगी। इन दो चीजों पर सरकार का सबसे अधिक फोकस रहेगा। भारत की विकास दर 7 से 8 फीसदी के बीच बनी रहेगी। वहीं महंगाई भी (Inflation) काबू में रहेगी।'

विदेशी निवेशक वापसी करेंगे

लोकसभा चुनाव की शुरुआत के बाद से ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इससे जुड़े सवाल ने पर रिद्धम ने कहा, 'फिलहाल मार्केट में दो बड़े खिलाड़ी हैं, पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स। अभी घरेलू निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। इस तरह के माहौल में विदेशी निवेशक चांस नहीं लेना चाहते। जैसे ही कॉर्पोरेट्स पैसा जुटाना शुरू करेंगे, विदेशी निवेशक भी मार्केट में एंट्री लेने लगेंगे। उनकी खरीदारी अगले 6 महीने में शुरू हो सकती है।' इक्विटी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो मई में 34,697 करोड़ रुपये हो गया। यह इससे पिछले महीने के मुकाबले 83.42 फीसदी अधिक है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार बनाएगी 3 करोड़ नए घर, क्या आप उठा सकते हैं योजना का लाभ

Pradhan Mantri Awas Yojana सोमवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रधान मंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने की मंजूरी मिल गई। वर्ष 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना लॉन्च की थी। आइए जानते हैं कि पीएम आवास योजना के लिए पात्रता मापदंड क्या है? पढ़ें पूरी खबर..

नई दिल्ली। सोमवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रधान मंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने की मंजूरी मिल गई। पीएम आवास योजना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 4.21 करोड़ मकान बनाए हैं।

केंद्र सरकार के इस फैसले पर श्री प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक एवं चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड ने कहा एक विजनरी कदम उठाते हुए नवगठित कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। यह रसभी के लिए घरर (हाउसिंग फॉर ऑल) के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है, और इससे पहले की 'क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम' (सीएलएलएस) की तुलना में इस बार पीएमएवाई-शहरी के तहत कार्पेट एरिया की योग्यता में वृद्धि की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है

वर्ष 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना लॉन्च की थी। देश में सभी के पास आवास हो इस उद्देश्य से सरकार ने यह योजना शुरू की थी। वर्ष 2015 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा कि थी आने वाले 5 साल में सरकार योजना के तहत 2 करोड़ नए घर बनाएगी।

पीएम आवास योजना (PMAY) देश के कमजोर वर्गों, शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। बजट 2023 में सरकार ने पीएम आवास योजना के फंड को 66 फीसदी बढ़ा दिया।

किसे मिलता है योजना का लाभ

पीएम आवास योजना का लाभ लो इनकम ग्रुप (LIG), मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) और EWS को मिलता है। EWS में वह लाभार्थी शामिल होते हैं जिनकी सालाना आय 3 रुपये तक होती है।

100 दिनों के सरकार के अजेंडे पर सरकार का फोकस, आयुष्मान योजना को लेकर जे पी नड्डा ने की अधिकारियों के साथ बैठक

सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ देने को अपने सौ दिन के एजेंडे में प्रमुखता से रखा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों को इस एजेंडे पर फोकस करने को कहा है। वहीं अमित शाह एस. जयशंकरअश्विनी वैष्णव ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत ज्यादातर मंत्रियों ने अपना कार्यभाल संभालते हुए मोदी सरकार की 10वर्ष की नीतियों की निरंतरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई।

नई दिल्ली। मंत्रालयों के बंटवारे के अगले ही दिन मंगलवार को मोदी 3.0 के मंत्री मोर्चे पर जुट गए। भाजपा और सहयोगी दलों के अधिकांश मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाल लिया। सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ देने को अपने सौ दिन के एजेंडे में प्रमुखता से रखा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों को इस एजेंडे पर फोकस करने को कहा है।

वहीं, अमित शाह, एस. जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत ज्यादातर मंत्रियों ने अपना-अपना कार्यभाल संभालते हुए मोदी सरकार की 10 वर्ष की नीतियों की निरंतरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी जैसे कुछ मंत्री बुधवार या गुरुवार को कार्यभार संभालेंगे।

इन योजनाओं पर नड्डा का फोकस

पांच वर्ष बाद स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे जेपी नड्डा ने कार्यभार संभालने के बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान जैसी मोदी सरकार के प्राथमिकता वाले योजनाओं की समीक्षा की। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे की प्रमुख प्राथमिकताओं में नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यू-विन पोर्टल को पूरे देश में लागू करना भी शामिल है। इसी तरह अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना एवं प्रसारण दोनों मंत्रालयों का कार्यभार संभाल लिया।

रेलवे के आधुनिकरण को नई दिशा

अपने पहले कार्यकाल में वैष्णव ने रेलवे के आधुनिकरण को नई दिशा दी थी। दूसरी बार पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद शिवराज ¨सह चौहान ने किसान कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताया।

अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में किसान सम्मान निधि की राशि जारी करके प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि कृषि और किसान सरकार के लिए काफी अहम हैं। महिला और बाल विकास विभाग का कार्यभार संभालने के बाद अन्नपूर्णा देवी ने नारी की नेतृत्वकारी भूमिका के स्वर्णिम सफर की शुरुआत का आह्वान किया। राजग में शामिल अन्य सहयोगी दलों के मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया। जदयू के ललन ¨सह ने पशुपालन व पंचायती राज, चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण, जीतन राम मांझी ने मध्यम व लघु उद्योग और एचडी कुमारस्वामी ने भारी उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया।

देश की सुरक्षा के लिए निरंतर काम करता रहेगा गृह मंत्रालय: शाह

अमित शाह ने लगातार दूसरी बार गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि उनका मंत्रालय देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर काम करता रहेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मोदी 3.0 में देश की सुरक्षा नीतियों एवं प्रयासों को नई ऊंचाई मिलेगी और आतंकवाद व नक्सलवाद के विरुद्ध देश एक मजबूत शक्ति बनकर उभरेगा। कार्यभार संभालने के पहले शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल लिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था।

कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो होंगे अगले सेना प्रमुख, 30 जून को लेंगे मनोज पांडे की जगह

सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। उपेंद्र द्विवेदी फिलहाल उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मालूम हो कि उपेंद्र द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर में सेवाएं दी हैं। इसी साल 19 फरवरी को उपेंद्र द्विवेदी ने थल सेना के उपप्रमुख का पदभार ग्रहण किया था।

सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे।

Army Chief बनने की दौड़ में थे सबसे आगे

उपेंद्र द्विवेदी फिलहाल उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मालूम हो कि उपेंद्र द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर में सेवाएं दी हैं। इसी साल 19 फरवरी को उपेंद्र द्विवेदी ने थल सेना के उपप्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। सेना उप प्रमुख बनाए जाने के बाद से ही लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे।

संभाल चुके हैं कई अहम जिम्मेदारी

मालूम हो कि रीवा सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी (Lt General Upendra Dwivedi) को 1984 में 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में नियुक्त किया गया था, इस इकाई की उन्होंने बाद में कमान संभाली। उनको उत्तरी और पश्चिमी दोनों थिएटरों के संतुलित इक्सपोशर का अनूठा गौरव प्राप्त है।

सांसद एसपी सिंह बघेलजी का दूसरा कार्यकाल आगरा के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा : फिल्म निर्माता सावन चौहान

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट पर एसपी सिंह बघेल ने दूसरी बार जीत दर्ज की है। उन्हें राज्यमंत्री का प्रभार मिला है। रविवार को एसपी सिंह बघेल ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली हैं। उसके बाद तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी, साथ ही आगरा के फ़िल्मि निर्माता सावन चौहान ने भी उन्हें नए कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

इस ऐतिहासिक अवसर पर फ़िल्मि निर्माता सावन चौहान ने कहा कि आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, सशक्त, सक्षम आदरणीय सांसद एसपी सिंह बघेलजी को लगातार दूसरी मोदी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। हमें आशा है कि आपका नया कार्यकाल आगरा के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सांसद एसपी सिंह बघेलजी की अविराम साधना का ही प्रतिफल है कि पिछले 10 वर्षों में आगरा का नव उत्थान हुआ है। गरीब, महिला, युवाओं के साथ ही आगरा के वंचित वर्ग का जीवन आसान हुआ है। विरासत, विकास व विश्वास को संजोए यह अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक उपलब्धि आगरा और एनडीए परिवार को गौरवभूषित तथा हर्षित करने वाली है। आगरावासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए साधनारत बघेल जी का यह कार्यकाल निःसंदेह आत्मनिर्भर भारत-विकसित भारत की संकल्पना को साकार करते हुए आगरा के विकास में स्थापित करने वाला सिद्ध होगा।

आपके निरंतर नेतृत्व में भारत विकास और समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहेगा और आपके कुशल नेतृत्व में हमारा आगरा विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तथा आगरा के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। आपके उत्कृष्ट नेतृत्व में आगरा की विकास यात्रा को नई गति एवं नई शक्ति मिलेगी। दीर्घकालिक कार्यकाल के लिए आदरणीय सांसद जी को अनेकों मंगलकामनाएं।

श्री चौहान ने आगे कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सांसद एसपी सिंह बघेल जी का दुसरा कार्यकाल विकसित आगरा के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा। निश्चित रूप से बघेल जी के सशक्त नेतृत्व में आगरा बड़ी आर्थिक शक्ति बन कर उभरेगा और आगरा वासियों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगा। श्री बघेलजी के नेतृत्व में आगरा ने परिवर्तनकारी परिवर्तन देखे हैं, और उनके लगातार दूसरे कार्यकाल में आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हम आगरा की एकता को मजबूत करने, सतत विकास को आगे बढ़ाने और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों को देखने के लिए तत्पर हैं। आगरा के मतदाताओं को अपने महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए बधाई।

10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया लोगों को संदेश; वीडियो भी किया शेयर

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का मंगलवार को आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा इस वर्ष योग दिवस करीब आ रहा है। यह जरूरी है कि हम योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने तथा दूसरों को भी इसे अपने- अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दोहराएं।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का मंगलवार को आह्वान किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, 10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर दुनियाभर के लाखों लोगों को एकजुट किया है।

10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : पीएम मोदी ने कहा, इस वर्ष योग दिवस करीब आ रहा है। यह जरूरी है कि हम योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने तथा दूसरों को भी इसे अपने-अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दोहराएं। योग हमें जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और धैर्य के साथ करने में सक्षम बनाता है। पीएम मोदी ने विभिन्न योगासनों और उनके लाभों को दिखाने वाले वीडियो भी साझा किए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है।

निरंतरता, अनुभव और उत्साह का संगम है केंद्रीय मंत्रिमंडल

प्रो. संजय द्विवेदी

केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह और अमित शाह इस सरकार के संकटमोचक हैं। राजनाथ सिंह के साथ जहां सहयोगी दलों का शानदार संवाद है, वहीं अमित शाह अपने कुशल राजनीतिक प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। इस सरकार में सहयोगी दलों के 11 मंत्री हैं।

केंद्र सरकार का नया मंत्रिमंडल निरंतरता की गवाही देता है। यह बात बताती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी टीम पर भरोसा कायम है। प्रमुख विभागों में अपनी आजमाई जा चुकी टीम को मौका देकर मोदी ने बहुत गंभीर संदेश दिए हैं। मंत्रिमंडल में अनुभव, उत्साह और नवाचारी विचारों के वाहक नायकों को जगह मिली है।

अनुभवी सरकार:

यह मंत्रिमंडल गहरी राजनीतिक सूझबूझ वाले नायकों से संयुक्त है। लंबे समय तक राज्य सरकारों को चलाने वाले 7 पूर्व मुख्यमंत्री इस सरकार में शामिल हैं। कैबिनेट में नरेंद्र मोदी सहित सात पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। जिनमें मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह (उप्र), शिवराज सिंह चौहान (मप्र), जीतनराम मांझी (बिहार), एचडी कुमारस्वामी (कर्नाटक), मनोहरलाल खट्टर (हरियाणा), सर्वानंद सोनोवाल (असम) मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत सरकार के विदेश सचिव और पिछली सरकार में विदेश मंत्री रह चुके एस.जयशंकर अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। आईएएस अधिकारी रहे अश्विनी वैष्णव अटलबिहारी वाजपेयी सरकार में उनके सचिव रहे,विविध अनुभव संपन्न वैष्णव सरकार में नवाचारों के वाहक हैं। पिछली सरकार उनके प्रदर्शन की गवाही है। इसी क्रम में नौकरशाह रहे हरदीप सिंह पुरी सरकार की शक्ति हैं। नितिन गडकरी का महाराष्ट्र सरकार से लेकर अब केंद्र में 10 साल का कार्यकाल सबकी नजर में है। देश में हुई परिवहन और सड़क क्रांति के वे वाहक हैं। वे केंद्र में सबसे लंबे समय तक परिवहन मंत्री रहने का रिकार्ड बना चुके हैं।

भाजपा के पास अनुभवी मंत्रियों की टीम सरकार के संकल्पों की वाहक बनेगी, इसमें दो राय नहीं। धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, जोएल ओराम, गजेंद्र सिंह शेखावत, डा. वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी हस्ताक्षर बन चुके हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रभावी संचालन का रिकार्ड इनके नाम है।

सरकार के संकटमोचक:

केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह और अमित शाह इस सरकार के संकटमोचक हैं। राजनाथ सिंह के साथ जहां सहयोगी दलों का शानदार संवाद है, वहीं अमित शाह अपने कुशल राजनीतिक प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। इस सरकार में सहयोगी दलों के 11 मंत्री हैं। जबकि 2014 में 5 और 2019 में सहयोगी दलों के 4 मंत्री शामिल थे। यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार में कुशल प्रबंधन की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। आने वाले समय में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव भी होने हैं। यही इस सरकार का पहला सार्वजनिक टेस्ट भी है।

मंत्रिमंडल में प्रतिबद्धता, निरंतरता और वरिष्ठता का ख्याल रखते हुए भी युवाओं को खास मौके दिए गए हैं। इसके साथ ही यह अखिल भारतीय चरित्र की सरकार भी है, केरल, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक का प्रतिनिधित्व इस सरकार में है। पांच अल्पसंख्यक समुदायों से भी सरकार में मंत्री बने हैं। साथ ही सामाजिक समरसता की दृष्टि से यह समावेशी सरकार कही जा सकती है। अभी तक की स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सुशासन को लेकर सरकार पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन समान नागरिक संहिता, मुस्लिम आरक्षण, जातीय जनगणना, राज्यों को विशेष दर्जा जैसे मुद्दे मतभेद का कारण जरूर बनेंगे। प्रधानमंत्री के कद और उनकी छवि जरूर इन साधारण प्रश्नों से बड़ी है। सरकार के प्रबंधक इन मुद्दों से कैसे जूझते हैं, यह बड़ा सवाल है। सहयोगी दलों के साथ संतुलन और उनकी महत्ता बनाए रखते हुए चलना सरकार की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह अपने अभिभावकत्व और नेतृत्व से एनडीए को संभालते हुए काम प्रारंभ किया है। वे आसानी से साधारण विवादों का हल भी निकाल ही लेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com

(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023